RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

12 वर्ष

दैनिक
सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, रविवार ●28 जुलाई , 2024 वर्षः-12 अंक-91 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

प्रदेश के 400 सरकारी स्कूलों में अब तक जीरो एडमीशन !

क्लास 1 से 10 तक बुरे हाल, सरकार पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

भोपाल। प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। लिटरेसी कैंपेन में सुधार के संबंध में राज्य सरकार के बड़े-बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कई स्कूलों में इस एकेडमिक ईयर में जीरो एडमिशन दर्ज किया गए हैं। राज्य भर में कम से कम 400 सरकारी स्कूलों ने इस साल कक्षा 1 से कक्षा 10 तक जीरो प्रवेश की सूचना दी है। इनमें से कुछ राज्य की राजधानी भोपाल सहित बड़े शहरी केंद्रों में हैं। इस चिंताजनक स्थिति को राज्य सरकार के ध्यान की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने संसाधनों के आवंटन को बैलेंस करने से लेकर कई और कामों के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसका यह परिणाम हुआ है। राज्य में

संचालित लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों में से अधिकांश प्राथमिक विद्यालय हैं। ये अपने प्रारंभिक सालों में छोटे बच्चों की एकेडमिक जरूरतों को पूरा करते हैं। जीरो एडमीशन की चिंताजनक स्थिति केवल प्राथमिक विद्यालयों तक ही सीमित नहीं है। इसमें 32 सेकेंडरी स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। इनमें आम तौर पर 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित सागर जिला सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र के रूप में उभरा है। यहां शून्य प्रवेश की समस्या से जूझ रहे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। हैरानी की बात है कि राज्य की राजधानी भोपाल भी इस परेशानी से अछूती नहीं रही है। भोपाल के कुल छह स्कूलों ने जीरो एडमीशन की सूचना दी है। इस समस्या को सुधारने के लिए एक कठोर प्रयास की जरूरत है।

कारणों को पता करने में जूझ रहा शिक्षा विभाग

इस मुद्दे की इतनी गंभीरता के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में जीरो एडमिशन के व्यवहार के पीछे कारणों के बारे में स्पष्टता की कमी से जूझते दिख रहे हैं। इस समस्या के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी केके द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हमें इस समस्या के पीछे के कारणों के बारे में पता नहीं है। कारणों की पहचान करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है। यह बयान इन सरकारी स्कूलों में बच्चों एडमिशनों में कमी में योगदान देने वाले कारकों के गहन विश्लेषण की जरूरत को दिखा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

स्वीडन के पास मिला 170 साल पुराने जहाज का मलबा

- इसमें 100 शैम्पेन की बोतलें मौजूद
- शाही परिवारों को कीमती शराब देने साथ जाते थे पुलिसकर्मी

स्टॉकहोम (एजेंसी)। स्वीडन के पास बाल्टिक समुद्र में 19वीं सदी में डूबे जहाज का मलबा बरामद हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, यह जहाज शैम्पेन की बोतलों, मिनरल वॉटर और पोर्सीलेन (सेरेमिक) से भरा हुआ था। जहाज का मलबा स्वीडन के ओलैंड के 37 किमी दक्षिण में मौजूद था। यह जहाज 170 साल पहले डूबा था। मलबे को ढूंढने वाले पोलैंड के डाइवर स्टैचुरा ने बताया कि वे पिछले 40 सालों से बाल्टिक समुद्र में जहाजों

के मलबे की तस्वीरें लेते रहे हैं। यह पहली बार है जब उन्हें किसी जहाज पर शराब की 100 से ज्यादा बोतलें मिली हैं। स्टैचुरा की कंपनी की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया कि जहाज का मलबा बहुत ही अच्छी हालत में था। शैम्पेन क्ले से बनी बोतलों में थी जिस पर सेल्टर्स ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ था। यह 19वीं सदी में जर्मनी के सबसे बेहतरीन शैम्पेन ब्रांड्स में से एक था। आमतौर पर इनकी शराब को शाही परिवार खरीदते थे।

राहुल का नया ठिकाना बंगला नंबर-5

- प्रियंका उनका घर देखने पहुंची, लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पुराना घर छोड़ा था

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने नया बंगला अलॉट किया है। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 राहुल का नया आशियाना हो सकता है। 26 जुलाई को राहुल यह बंगला देखने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी राहुल का यह घर देख चुकी हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप-8 बंगला

ऑफर किया है। इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, स्टडी रूम, 1 सर्वेंट क्वार्टर है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल को 3-4 बंगलों के ऑप्शन दिए गए थे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपथ स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। ये दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित टाइप-8 बंगला है, जो हाइएस्ट कैटेगरी है।

पहले पुतिन को साधा अब जेलेंस्की की बारी

पीएम मोदी की सफल कूटनीति,अगस्त में जाएंगे यूक्रेन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा के बाद अब अगले महीने (अगस्त) यूक्रेन का दौरा करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पीएम की यह पहली यात्रा होगी। इससे पहले इटली में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की भेंट हुई थी। तब दोनों नेताओं ने गले लगकर गर्मजोशी से एक-दूसरे का स्वागत किया था। जेलेंस्की ने मोदी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने पर बधाई भी दी थी। माना जा रहा है कि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर निकल सकते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों के बाद तीसरा कार्यकाल हासिल किया, उस दिन जेलेंस्की ने उन्हें बधाई दी थी और युद्धग्रस्त देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और देश के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया तथा चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हरसंभव प्रयास करता रहेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत का कहना रहा है कि इसका समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही हो सकता है, तथा प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत किसी भी शांति प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है।

वन्य प्राणी रेस्क्यू में रायसेन के 10 कर्मचारी होंगे सम्मानित

- वर्ल्ड टाइगर डे पर सीएम मोहन करेंगे 19 वन अफसरों, कर्मचारियों का सम्मान

भोपाल। वर्ल्ड टाइगर डे पर 785 बाघों के साथ मध्यप्रदेश बाघ टाइगर डे मनाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में टाइगर डे के मौके पर वन विभाग के हित में कोई नया ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर वन विभाग के

अफसरों के साथ मंथन भी हो रहा है। वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी इस दौरान फारेस्ट अफसरों के साथ मौजूद रहेंगे। टाइगर डे पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन एमपी टाइगर फाउंडेशन समिति द्वारा किया जा रहा है जिसमें टाइगर रिजर्व के सभी क्षेत्र संचालक मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व एरिया में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर संकट में बीजेपी

- शिंदे-पवार के प्रेशर को संभालना हो रहा मुश्किल, हार ने बिगाड़ा गणित

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुए हैं। अब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर वहां की सभी पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन भी तैयारी में है लेकिन तीनों पार्टियों के बीच सीट बटवारें को लेकर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है।

हालांकि बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट करना आसान नहीं है। जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने पास किसी भी हाल में 150 सीटें रखना चाहती है। जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 100 से कम सीट देने का प्लान है। हालांकि शिंदे 100 से कम पर तैयार होने वाले नहीं है। वहीं राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी किसी भी हाल में 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

हर ओर 'जल' जला, 17 राज्यों में भारी बारिश

● पानी-पानी हुए एमपी-राजस्थान, गुजरात-महाराष्ट्र के बुरे हाल ● उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली में दुकानें बालगंगा नदी में गिरीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित शाहबाज में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में तीन लोग मलबे में दब गए।

इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस, फायर बिग्रेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। घटना शनिवार तड़के साढ़े चार बजे हुई। इधर, गुजरात के भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2200 लोग नवसारी और 500 लोग तापी जिले के हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से

यमुनोत्री धाम के दोनों गर्मकुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर का ऑफिस, रसोई टूट गई है, मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। भारी मलबा और बोल्डर से यमुनोत्री मंदिर को भी नुकसान हुआ है।

जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राममंदिर के निकट रजिस्ट्रेशन केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। गुजरात के नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान (23 फीट) से 5 फीट ऊपर बह रही है। इससे शहर का 30 फीसदी हिस्सा पानी में डूब गया है। यह तस्वीर नवसारी में बने रेलवे फ्लाईओवर की है। मध्यप्रदेश में लो प्रेशर एरिया (कम दबाव क्षेत्र) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम ऐक्टिव है, जिससे 18 जिलों में बारिश हुई। शनिवार को विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, जबलपुर और बालाघाट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अगले चार-पांच दिन लगातार बारिश का दौर रहेगा। आज 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 28 जिलों में येलो अलर्ट है। राजस्थान में अब तक 185.3 एमएम औसत बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 1 फीसदी कम है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

कांग्रेस से भाजपा में आए नए नवेले मंत्री के साथ बड़ा फ्रॉड !

संगठन महामंत्री बनकर 500000 मांगे लेकिन एक चूक हो गई

भोपाल। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत के साथ एक ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी में बड़ा पद देने के नाम पर 500000 की डिमांड की गई थी। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामनिवास रावत ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्रा से कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि उनके साथ फ्रॉड कॉल किया जा रहा है। उनके निर्देशों पर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके मोबाइल नंबर पर कुछ दिन पहले कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बताया था। बात करने पर कॉलर ने कहा कि विजयपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में आपके लिए कुछ लोगों की व्यवस्था कर देंगे जो आपका पूरा काम भी देखेंगे, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से आपको 500000 लगेंगे। इस पर रावत ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई बार कॉल आया तो रावत ने इसकी शिकायत की।

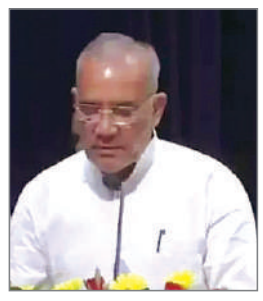

बताया जा रहा है कि रावत को आए कॉल में जो व्यक्ति बात कर रहा था वह खुद को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डी संतोष का पर्सनल सेक्रेटरी बता रहा था, जबकि संगठन महामंत्री का नाम बीएल संतोष है। यहीं पर मंत्री रावत को शक हो गया और उन्होंने पुलिस को यह बात बताई।

कोर्ट ने जिसे तड़ीपार किया वो आज देश का गृहमंत्री

शरद पवार ने कहा-हमें इसके बारे में अब सोचना ही होगा

शाह ने 6 दिन पहले पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था

संभाजी नगर (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार के सरगना वाले बयान पर शरद पवार ने आज पलटवार किया। एनसीपी (एसपी) नेता पवार ने कहा- कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मुझ पर हमला किया और कुछ बातें कहीं। उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार (राज्य से बाहर) कर दिया था। अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में दो साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसी को लेकर शाह पर टिप्पणी की।

इससे पहले 21 जुलाई को एक इवेंट में शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं। अगर देश में किसी भी सरकार में किसी राजनेता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है, तो वह शरद पवार हैं, और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही थीं।

हैदराबाद जा रहा बकरियों से भरा ट्रक, जबलपुर हाइवे पर हुआ हादसा, 230 की मौत

दमोह। उत्तर प्रदेश से खरीदकर बकरियों को लेकर हैदराबाद जा रहा ट्रक जबलपुर हाइवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 230 बकरियों की मौत हो गई है। कई घायल हुई हैं। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामला बकरियों के ओवरलोड का भी बन रहा है।

दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह जबेरा थाना क्षेत्र की बिदारी घाटी में एक बकरियों से भरा ट्रक पलटने से 230 बकरियों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक एक अन्य वाहन को क्रॉस कर रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही जबेरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ट्रक में बकरियों को ओवरलोड करने का

मामला भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक स्रा-40ऱच-4177 उत्तर प्रदेश के महोबा से 500 बकरियों को लेकर हैदराबाद जा रहा था। जबेरा थाना क्षेत्र की विदरी घाटी के मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत बकरियों को सड़क किनारे से हटाया। ट्रक में कुल 500 बकरियां भरी हुई थीं, जिनमें से 230 की मौत हो गई और 170 बच गईं। कुछ बकरियां घायल हुई हैं। बकरियों के दस्तावेज ट्रक चालक के पास थे, लेकिन ट्रक में क्षमता से अधिक बकरियां भरी गई थीं। ये बकरियां महोबा, उत्तर प्रदेश के बाजार से खरीदकर हैदराबाद ले जाई जा रही थीं। ट्रक में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जबेरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद ही ट्रक को छोड़ा जाएगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मोहन सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है. बरगी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आज 28 जुलाई को बांध के गेट खोले जाएंगे इससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है. भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया है. बता दें कि राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। बारिश को देखते हुए सीएम मोहन यादव ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश खेती के लिए अच्छी है. लेकिन नदियों में बाढ़ की स्थिति और बांधों के गेट खोलने को लेकर हमारी सरकार तैयार और सतर्क है. फिलहाल आज भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शिवहर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, छतरपुर, सतना में भारी बारिश का अनुमान है. हम सब एहतियात बरत रहे हैं अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जिसके लिए राहत शिविर भी चलाए जा रहे है। सीएम ने आगे कहा कि एमपी के बांध 50 फीसदी भर चुके हैं बरगी का जलस्तर बढ़ रहा है,आज 28 जुलाई को गेट खोलने पड़ेंगे जिससे नर्मदा का जलस्तर बढ़ेगा. इसे देखते हुए नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन जिलों को अलर्ट कर दिया गया है इसके अलावा उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है भोपाल, रतलाम, गुना, उज्जैन, विदिशा, राजगढ़ समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है. मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में हो रही जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राजधानी भोपाल के कई इलाकों में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है. वहीं, कई इलाकों में लोगों के घरों में जलभराव हो गया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भोपाल समेत प्रदेश के इन जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

कांग्रेस नेता की अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान

पहले भी हो चुका है हादसा

भोपाल। राजधानी भोपाल में बैरसिया रोड स्थित लांबाखेड़ा में बनी कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की अगरबत्ती की फैक्टरी में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर लगते ही मौके पर पहुंची गांधीनगर, छोला, कबाड़खाना और फतेहगढ़ फायर स्टेशन की दमकलों ने आग पर काबू पाया।बता दें कि घटना रात तीन बजे की होना बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। नगर निगम के फायर फाइटर पंकज यादव ने बताया कि फैक्टरी में कुछ टूव्हीलर्स भी रखे थे, जो आग की चपेट में आने से बच गए। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग कैसे लगी, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लांबाखेड़ा इलाके में कांग्रेस के सीनियर नेता गोयल की पूजा-पाठ नाम से अगरबत्ती की फैक्टरी है। आग की वजह से खासा नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। आग की सूचना के बाद में ईंटखेड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसी फैक्ट्री में पहले आग लग चुकी है। करीब छह घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई है।

पहले भी फैक्ट्री में हो चुकी आगजनी

कांग्रेस नेता की फैक्ट्री में इससे पहले भी कई बार आगजनी की घटना हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। उस दौरान आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया गया गया था। हालांकि, इस बार आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

127 योजनाओं पर बिना अनुमति नहीं होगा भुगतान

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों में कटौती के बाद अब कई योजनाओं में भुगतान को लेकर शर्तें लगा दी हैं। वित्त विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें राम वन गमन पथ , मंत्रियों के आवास के साज-सज्जा समेत 127 योजनाओं के भुगतान को लेकर वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।संचालक बजट की तरफ से विभागों को जारी आदेश में वित्त विभाग की तरफ से समय समय पर जारी आदेश को पालन करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें कहा गया है कि यदि किसी योजना में बजट के बचत की संभावना हो तो उसकी जानकारी 15 जनवरी तक बताने को कहा गया है, ताकि दूसरी योजना में उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही आदेश में कहा गया है कि आरक्षित निधियों के भुगतान की कार्रवाई वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही की जाना सुनिश्चित किया जाए।

मंत्रियों के बंगलों में साज-सज्जा और नए निर्माण के लिए अनुमति जरूरी

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार के अनुसार राम वन गमन पथ अचल विकास योजना, मंत्रियों के बंगलों की साज सज्ज, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति क्रियान्वयन, नए मेडिकल कॉले और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा स्कूटी योजना, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, कायाकल्य अभियान, अमृत 2.0 जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना,किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, डॉ टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना, पीएम जनमन, लाड़ली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना समेत 46 विभाग की 127 से ज्यादा योजनाओं के भुगतान से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

रीवा को बड़ी सौगात अगस्त में पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन

रीवा। भाजपा सरकार ने केन्द्र के साथ-साथ राज्य में भी कई तरह के विकास कार्य किए हैं. मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने पर राज्य को कई तरह की सौगातें मिल रही हैं. देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के विकास कार्यों में प्रगति देखी गई है. आगामी दिनों में एमपी के रीवा) शहर को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं. अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छठे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो रीवा में स्थित है।

इस कार्यक्रम का संचालन वर्चुअली किया जाएगा. टेक्नोलॉजी के इस युग में ऑनलाइन ही इस एयरपोर्ट का शुभारंभ पीएम करेंगे. राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले के गोविंदगढ़ में हो रहे कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगस्त महीने में रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जाएगा. इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि गोविंदगढ़ में जल्द ही सफेद शेरों के ब्रीडिंग सेंटर का काम शुरू होगा. इस समारोह के बाद उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने 'एक पेड़ मां के नाम' की मुहिम के तहत गोविंदगढ़ थाना परिसर में पौधा लगाया राज्य के डिप्टी सीएम ने गोविंदगढ़ में एक समारोह के दौरान शहर के सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से कराए जाने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में सफेद शेरों के ब्रीडिंग सेंटर का काम शुरू होगा साथ ही उन्होंने रीवा में स्थित छुहिया घाटी में सड़क मार्ग और सुरंग बनाने की जानकारी साझा की. उन्होंने आगे कहा कि गोविंदगढ़ की पहचान सफेद शेर से है. महाराजा मार्तंड सिंह को याद करना गौरव की बात है विंध्य क्षेत्र में सफेद शेरों की वापसी हो गई है. जल्द ही गोविंदगढ़ में पूर्व से स्वीकृत सफेद शेर के ब्रीडिंग सेंटर का कार्य शुरू होगा. इसके साथ ही उन्होंने रीवा में होने वाले अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी दी और कहा कि अमिलकी की नहर की पुलिया के घुमाव को सीधा कराया जाएगा और गोविंदगढ़ घाट की सड़क का सुधार कार्य जल्द शुरू होगा उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं. मध्य प्रदेश जिस तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, उसी प्रकार प्रदेश के विकास में विंध्य क्षेत्र भी अपनी भूमिका निभा रहा है. रीवा जिले में बाणसागर की नहरों से तीन लाख एकड़ क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है. जिससे वहां के किसान आसानी से खेती कर रहे हैं. उन्होंने अपने भाषण में आगामी पांच वर्षों में 9 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देने की बात कही. बहुती नहर में 1500 करोड़ रुपये से और सीतापुर/हनुमना में 3500 करोड़ रुपये से सिंचाई सुविधा के कार्य को मंजूरी दी गई है।

एक कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण हटाये जायेंगे:कलेक्टर कोचर

कलेक्टर कोचर ने सुभाष कालोनी के पास से निकलने वाले नाले का लिया जायजा

दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर शनिवार सुबह सुभाष कालोनी पहुंचे। उन्होंने सुभाष कालोनी सहित यहां से निकलने वाले नाले का विस्तृत जायजा लिया और नगर पालिका अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। अभी कुछ दिन पहले हुई बारिश से यहां पर निवास करने वालों के जन जीवन पर असर पड़ा, पानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में मकानों में भर गया था, जिसकी शिकायत कालोनी निवासियों ने की थी। इसी का जायजा लेने आज कलेक्टर सुभाष कालोनी पहुंचे थे। उन्होंने श्याम नगर से किल्लाई मार्ग तक के नाले का जगह-जगह जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रितु पुरोहित सहित नगर पालिका का अमला, विक्रम सिंह ठाकुर, पंकज सेन, सहित सुभाष कालोनी सहित क्षेत्र के निवासी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री कोचर ने कहा यहां सुभाष कालोनी में दो तीन तरह की बड़ी समस्याएं हैं, पहली नालियों की सफाई

लगातार जारी है। आज फिर निर्देश दिये गये हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कचरा फंसा हुआ है, उसको निकाला जाये। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह अतिक्रमण की है क्योंकि लोगों ने नजूल की जमीन पर और नालियों को पैक करके उनके ऊपर निर्माण कर लिया हैं।

कलेक्टर श्री कोचर ने कहा एक कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण हटाएंगे, जब तक यह अतिक्रमण नहीं हटेंगे तब तक इस समस्या से राहत नहीं मिलेगी। तीसरा यहां ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र मिले हुए हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र वाला इलाका है, वहां पर भी थोड़ा काम करना है, बरसात कम होने के बाद वहां पर भी हम सफाई का काम शुरू किया जायेगा, जहां-जहां पानी रुकने के स्थान है, जिसके कारण से पानी रुक गया है, यहां पर अलग-अलग जगह से फ्लो होकर पानी काफी आता है, निकालने के लिए नालियां बहुत सकरी है, उस कारण से और नालियां इतनी डायवर्टेड है, समय-समय पर अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग कारणों से अलग-अलग डायवर्सन बनाए गए हैं, इसके कारण से पानी का पूरा फ्लो टूट जाता है और जगह-जगह लोग कचरा डाल देते हैं, जिससे पानी वहीं रुक जाता है और फिर मकानों में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा अतिक्रमण करने वालों को किसी कीमत बक?सा नहीं जायेगा, आम आदमी जिसने कुछ नहीं किया है उसको जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े इस पर काम किया जायेगा।

उपकाशी हटा में श्रावण माह में चल रहे अनेक धार्मिक आयोजन

हटा। नगर उपकाशी में श्रावण माह के अवसर पर शहर में धार्मिक आयोजित किए जा रहे हैं और नगर उपकाशी हटा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पन्या परिवार द्वारा आयोजित असंख्य शिवलिंग निर्माण पार्थिव अर्चन में बहुत से श्रद्धालुओं ने पहुंच कर विधि विधान के साथ सभी ने शिवलिंग निर्माण किया इस अवसर पर पंचांग पूजन के दौरान पंडित श्री वीरेंद्र शास्त्री के द्वारा विधिवत पूजन कराया गया। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के द्वारा दुग्ध जल धारा के साथ अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में यजमान पंडित शशांक पन्या रहे कार्यक्रम के समापन पर भव्य आरती के साथ धार्मिक कार्यक्रम का समापन किया गया रिमझिम बारिश में जलविहार किया गया।

मगरगच्छ के हमले से मृत बालक के उत्तराधिकारी को 08 लाख रूपये की क्षति पूर्ति राशि दी

दमोह। जिले के ग्राम हटरी में मगरमच्छ के हमले से नदी में लापता हुए बालक की मृत्यु होने पर वन मंडलाधिकारी एम.एस. उइके ने मृत बालक के पिता अर्जुन सिंह लोधी के खाते में 07 लाख 90 हजार की क्षतिपूर्ति राशि अंतरित की है। ज्ञातव्य है दमोह रेंज अंतर्गत घटित हुई घटना अनुसार ग्राम हटरी में किशन लोधी पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 08 वर्ष जब अपने पिता के साथ नदी में नहाने गया था, उसी समय अचानक मगरगच्छ के द्वारा हमला किया जिस कारण से किशन लोधी नदी के पानी में लापता हो गया था। खोजबीन करने पर बच्चे की मृत देह दूसरे दिन प्राप्त हुई थी। उक्त घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये वन मण्डलाधिकारी दमोह एम.एस.उइके ने दमोह रेंजर विक्रम चौधरी को निर्देश दिये और शासन के आदेश अनुसार वन्यप्राणी द्वारा जनहानि होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में 10 हजार रूपये की राशि मृत बच्चे के वैध उत्तराधिकारी बालक के पिता अर्जुन सिंह लोधी को तत्काल प्रदान की गई थी। इस प्रकार वन विभाग द्वारा मृत बालक के पिता को 08 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।

शनिवार शाम 4 बजे छोड़ा गया बांध के दो गेटों से 130 क्यूसेक पानी, बढ़ा नदी का जलस्तर

टीकमगढ़ । धसान नदी के ऊपरी हिस्से में बारिश के चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे बान सुजारा बांध में पानी बढ़ने शनिवार की शाम 4 बजे एक दफा फिर बांध के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा जाएगा। सप्ताह में दूसरी बार शनिवार को सुजारा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके चलते नदी के निचले हिस्से में 2 से 4 फीट जल स्तर बढ़ने की संभावना है। बान सुजारा बांध परियोजना के अनुविभागीय अधिकारी आरएस सेजवार ने बताया कि पिछले 48 घंटे से लगातार धसान नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिसके चलते आज शाम 4 बजे बांध के 2 गेट खोलकर 65 से 130 क्यूमेक्स पानी छोड़ जाएगा। जिससे धसान के जलस्तर में कुछ कमी आएगी । उन्होंने बताया कि डैम से पानी छोड़े जाने पर धसान नदी के निचले हिस्से में जल स्तर बढ़ जाएगा।

इष्ट के प्रति श्रद्धा प्राणी के कल्याण का सब से सरल साधन है

हटा। गायत्री शक्तिपीठ में महा शिव पुराण कथा के छठवें दिवस कथा वाचक पंडित प्रदीक मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा की क्रौच नामक पर्वत बाण नमक दैत्य से पीड़ित होकर कार्तिकेय जी के पास आकर प्रार्थना करने लगा कि हे कुमार तुम इस राक्षस से मेरी रक्षा करो । कुमार ने उस पर्वत की विनती को सुनकर अपनी अमोघ शक्ति का प्रहार करके क्षण मात्र में बाण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिससे उस कौंच नामक पर्वत का दुख दूर किया। इस स्थान पर कार्तिकेय जी ने भगवान शिव के तीन लिंगो प्रतिज्ञेशवर, कपालेश्वर महादेव, एवं कुमारेश्वर महादेव को स्थापित किया। यह तीनों लिंग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक जी वहां से आगे बड़े-तो वहां पर शिव जी का पुत्र कुमुद त्राहिमाम कहकर विनती करने लगा कि हे प्रभु ताड़कासुर का अनुगामी प्लंबासुर जो ताड़कासुर के वध के समय भाग गया था। वह अब अनेक उपद्रव करके मुझे कष्ट दे रहा है। शेष पुत्र कुमुद की विनती सुनकर शिवजी का स्मरण करके शक्ति का प्रहार कर दिया जिससे प्रलंबासुर का वध हो गया। शेष पुत्र कुमुद कार्तिकेय जी की जय जयकार करने लगा। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर गए एवं परिवार जनों के साथ आनंद से रहने लगे। कुछ समय बीता एक दिन माता पार्वती स्नान कर रह थी। नंदी द्वार पर बैठे हुए थे उस समय शिवजी नंदी को छिड़क कर भीतर चले गये पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। पार्वती जी के मन में आया कि स्वयं की रक्षा के लिए मुझे एक गण की उत्पत्ति करनी चाहिए यही विचार करते हुए एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, महापराक्रमी, महाबलशाली, बुद्धिमान एवं सुंदर बालक को उत्पन्न किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र गणेश हो इस प्रकार विध्नकर्ता गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि हमारा मन हमारे ईष्ट में लगा है तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता। गायत्री शक्तिपीठ में प्रतिदिन पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं लाखों की संख्या मे पार्थिव शिवलिंग निर्माण का रुद्राभिषेक हो रहा है। हजारों श्रद्धालु शिव पुराण कथा का श्रवण कर श्रावण मास में पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित महेश पुरानी मनीष पल्या ने पहुंचकर कथावाचक जी का स्वागत किया और धर्म लाभ अर्जित किया, पंडित राम किशोर दुबे ने स्वागत किया।

सरपंच संघ ने किया विधायक यादवेंद्र सिंह का सम्मान

टीकमगढ़। प्रदेश सरकार के द्वारा मनरेगा निर्माण कार्य योजना के निमयों में परिवर्तन किया गया था। जिसकें संबंध में विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ सहित संपूर्ण जिले के सरपंचों ने टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्र सिंह को मनरेगा निर्माण कार्य नियमों में परिवर्तन के संबंध में अवगत कराया। जिसके फलस्वदरूप विधायकने विधानसभा सत्र के दौरान मनरेगा निर्माण कार्यादेश में सुधार किये जाने के लिए विधानसभा मंच के माध्येम से सदन में सरकार को घेरा एवं विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचायत मंत्री को अवगत कराया।

इसके बाद संपूर्ण मप्र के सरपंचों ने 23 जुलाई को भोपाल में मनरेगा नियमों के विरूद्ध प्रदर्शन किया और सरकार ने मनरेगा नियमों में संशोधन कर पूर्व की तरह निर्माण कार्य कराये जाने का आश्वेसन दिया। उक्त मनरेगा नियमों में सुधार कराने में टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्रा सिंह जी की महत्व पूर्ण भूमिंका रही जिसके लिए समस्तम सरपंचों ने विधायक निवास पर आकर विधायक को धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर सरपंच संघ टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र यादव अंतौरा, करन यादव सरपंच बड़माड़ई, शिवचरन लोधी सरपंच दरी, मानसिंह लोधी सरपंच राधापुर, घनेन्द्र यादव सरपंच रानीपुरा, रामेश्वचर यादव सरपंच प्रतिनिधि मामौन, सरदार यादव सरपंच बडागांव खुर्द, पुष्पेमन्द्र यादव सरपंच प्रतिनिधि अस्तौन, दिनेश अहिरवार सरपंच आलमपुरा सहित समस्तर सरपंचगण उपस्थित रहे। सभी ने ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक विकास कार्य कराने का संकल्प लिया साथ ही विधायक ने ग्राम के विकास में किसी प्रकार की कमी न रहने का आश्वरसन दिया।

विधायक ने किया धन्यवाद ज्ञापित– टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्र सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा जिले के सीएम राइज विद्यालयों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने पर धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने पत्र द्वारा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग) से कहा है कि टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके द्वारा दिए गए सीएम राइज विद्यालयों के प्रस्तावों में से चार को स्वीकृति प्रदान की है।

दैनिक
सद्भावना पाती
...प्राणियों में सद्भावना हो...
इंदौर पाती
3
इंदौर, रविवार 28 जुलाई , 2024

राजवाड़ा पर वाहन धोना पड़ा महँगा

इंदौर। इंदौर के प्रतिष्ठित राजवाड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपने चार पहिया वाहन को धोना महंगा पड़ गया। यह घटना राजवाड़ा स्थित एसबीआई शाखा के सामने की है, जहां एक व्यक्ति अपने वाहन को नर्मदा के पानी से धो रहा था। इस दौरान धोने का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी होने लगी। नागरिकों ने तुरंत इस मामले की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद रूपाली पेंडरकर से की पार्षद रूपाली पेंडरकर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को सूचित किया। इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति का 1000 रुपये का चालान काट दिया। यह घटना शहर के नागरिकों के जागरूकता और सतर्कता का उदाहरण है, जिसने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने से रोका। नगर निगम ने भी इस कार्रवाई के माध्यम से साफ संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इंदौर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बदलना तय

इंदौर। शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बदलना तय हो गया है फैसले पर किसी भी दिन मुहर लग सकती है और सुरजीतसिंह चड्ढा को हटाकर नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है भोपाल से जारी हुए नोटिस की राजनीति के बाद वरिष्ठ नेताओं ने भी लगभग इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है माना जा रहा है कि इंदौर में 6 अगस्त को होने वाले धरने-प्रदर्शन के बाद आदेश जारी हो सकते है जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव का हटना भी तय है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कई तरह के आरोप भी लगे और कोई बड़ी उपलब्धि भी सामने नहीं आई है अब चूंकि उनका दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया है तो उनका हटना तय है, लेकिन शहर अध्यक्ष सुरजीतसिंह चड्ढा का कार्यकाल अभी एक साल का ही हुआ है, लेकिन उन्हें हटाना भी तय हो गया है पिछले दिनों गांधी भवन में भाजपा सरकार के मंत्री कैलश विजयवर्गीय और अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करने के मामले में वे प्रदेश कांग्रेस के हाशिए पर आ गए हैं दिग्गी गुट से आने वाले चड्ढा के लिए पटवारी और दिग्गी ने भी दम लगाया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्रसिंह की सख्ती के चलते अब वरिष्ठ नेताओं ने सुरजीत को हटाने पर सहमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार किसी भी दिन आदेश जारी हो सकते हैं, लेकिन 6 अगस्त को इंदौर में नगर निगम पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को लेकर प्रदेश संगठन अभी चुप है और हो सकता है कि अगले महीने ही यह बदलाव हो। सुरजीत के हटने की खबर के बाद शहर कांग्रेस की कुर्सी के दावेदार अमन बजाज, अरविंद बागड़ी, राजू भदौरिया, देवेंद्र सिंह यादव और पिंटू जोशी ने दौड़-भाग तेज कर दी है संगठन युवा चेहरे को इंदौर की कुर्सी पर बिठाना चाहता है,ताकि वह सबको साथ लेकर चल सके।

कई शहरों के लिए पहली बार बस सेवा, इंदौर से अयोध्या, काशी सहित 17 शहरों के लिए शुरू होंगी लक्जरी बसें

इंदौर। इंदौर से देश के प्रमुख शहरों के लिए जल्द ही लक्जरी बस सेवा मिलेगी। इन बसों का संचालन अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) द्वारा किया जाएगा। बसों का संचालन इंदौर से अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली सहित 17 शहरों के लिए किया जाएगा। एआईसीटीएसएल जल्द ही बसों के संचालन के टेंडर जारी करने जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि ये बसें तीन से चार माह में शुरू हो जाएंगी।

अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के पहले से एआईसीटीएसएल प्रबंधन इंदौर से अयोध्या सहित देश के प्रमुख शहरों में बसें चलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए दो बार टेंडर भी जारी हुए, लेकिन ऑपरेटर्स न मिल पाने के कारण बसें शुरू नहीं हो पाईं। इसे देखते हुए एआईसीटीएसएल ने टेंडर शर्तों में कुछ बदलाव के साथ ही कुछ नए शहरों को भी जोड़ते हुए बसें चलाने के लिए दोबारा टेंडर तैयार किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में टेंडर जारी होंगे और तीन से चार माह में बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

एआईसीटीएसएल लंबे समय से इंटरस्टेट स्काय बसों का संचालन कर रहा है, लेकिन नए टेंडर में कई नए शहरों को पहली बार जोड़ा जा रहा है। इनमें अयोध्या, वाराणसी (काशी), दिल्ली, पुणे, राजकोट, रायपुर, कानपुर, कोटा, बांसवाड़ा, भुसावल और शहडोल प्रमुख हैं। इन बसों के शुरू होने से मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ ही इंदौर से यात्रियों को देश के प्रमुख राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा मिल सकेगी।

दूरी के हिसाब से अलग सीटिंग

अधिकारियों ने बताया कि 17 शहरों के लिए कुल 42 बसें चलाई जाएंगी ये बसें गंतव्य के पहले के सिर्फ कुछ ही स्थानों पर रुकेंगी, जिससे यह गंतव्य तक पहुंचने में अपेक्षाकृत कम समय लेंगी ये बसें वातानुकूलित (एसी) होने के साथ ही अत्याधुनिक होंगी बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस, कैमरे, पैनिक बटन, फायर अलार्म जैसी कई सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही ये बसें काफी आरामदायक भी होंगी। बसों में रूट की दूरी के हिसाब से सीटिंग भी होगी जैसे सामान्य सीटिंग, सेमी स्लीपर सीटें और स्लीपर कैटेगरी की सीटें होंगी एआईसीटीएसएल द्वारा इंदौर से इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसें चलाने के लिए पहले भी दो बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन ऑपरेटर्स न मिल पाने के कारण बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर अब दोबारा टेंडर शर्तों में कुछ बदलाव के साथ टेंडर तैयार किए गए हैं इसका उद्देशय इंदौर से धार्मिक पर्यटकों के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है कुछ ही दिनों में टेंडर जारी किए जाएंगे इसमें 17 शहरों के लिए 42 बसें चलाने की योजना है। टेंडर जारी होने के बाद जल्द ही बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी

(ऋतुराज बुड़ावनवाला)

पथराव की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा

खाचरौद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रतलाम के पास बढ़ती पथराव की घटनाओं के मद्देनजर यहां अलग-अलग पांच स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव एसपी राहुल लोढ़ा के निर्देशन में तैयार किया गया है,जो शासन को भेजा जाएगा। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए एक्सप्रेस-वे पर पुलिस चौकी भवन बनाकर बल तैनात किया जाएगा। इससे वहां 24 घंटे पुलिस की उपलब्धता रहेगी और वाहन चालकों व यात्रियों को घटना-दुर्घटना होने पर तत्काल पुलिस की मदद मिलेगी। एक्सप्रेस-वे पर अभी तक एक भी पुलिस चौकी नहीं है। इस कारण पथराव की घटना होने पर संबंधित थाने से पुलिस को घटना स्थल पहुंचने पर समय लगता है व कई थानों में स्टाफ की कमी के चलते पुलिस पर्याप्त पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है। इन

घटनाओं को रोकने के लिए यहां पुलिस चौकियां खोलने की तैयारी है। इन चौकियों में 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस-वे के मध्य प्रदेश के 224 किमी के हिस्से में करीब एक साल से आवागमन शुरू हो गया है। मंदसौर, रतलाम व झाबुआ जिले के लिए वाहन प्रतिदिन गुजर रहे है। इस मार्ग पर वाहनों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर खासतौर पर रावटी व शिवगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा वाहनों पर पथराव किया जा रहा है। पिछले एक साल में अनेक बार वाहनों पर पथराव किए गए। 13 व 14 जुलाई की दरमियानी रात भी कई वाहनों पर पथराव किया गया था। बदमाशों द्वारा किए पथराव में एक ट्राले और 5 कारों को नुकसान हुआ। एक वाहन में सवार जितेंद्र पाटीदार भी इस पथराव में घायल हो गए थे। गत एक वर्ष में रावटी ब्रिज व शिवगढ़ के ग्राम बायडी तथा झाबुआ जिले से लगे क्षेत्रों में कई बार पथराव की घटनाएं हो चुकी है। एक फरवरी 2024 को पूर्व विधायक दिलीप मकवाना के स्कॉर्पियो वाहन पर रावटी के समीप पथराव किया गया था, जिससे वे बाल-बच गए।

इंदौर के कई इलाकों में हल्की बारिश

सुबह से छाए रहे बादल; जुलाई के बचे चार दिनों में माह का कोटा पूरा होना मुश्किल

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में शनिवार सुबह से बादल छाने के साथ कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो हुई। वहीं पिछले 10 दिनों से मौसम ऐसा है कि रोज बादल छा रहे हैं। इसके साथ फुहारें, रिमझिम और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो रही है लेकिन झड़ी जैसा मौसम नहीं है। स्थिति यह है कि इस सीजन की अब तक साढ़े दस इंच ही बारिश हुई है। माह खत्म होने में चार दिन बाकी है। अभी जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है उस लिहाज से इस बार जुलाई का 14 इंच का कोटा पूरा होना मुश्किल है। पिछले साल इस दौरान सीजन की 20 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। रोज हो रही रिमझिम से मौसम में ठण्डक जरूर घुली है लेकिन इंदौर में जुलाई का मिजाज जो रहा है वह इस बार नहीं है। अभी दिन का तापमान 26.8 (-2) डिग्री और रात का तापमान 23.6 (+1) डिग्री सेल्सियस बना हुआ है।

इंदौर के विनय तिवारी की नीट (यूजी) में 96 रैंक

पहले 201 रैंक थी, अपडेट रिजल्ट में अंडर 100 में मिला स्थान

इन्दौर (एजेंसी)। नीट (यूजी) 2024 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से अपडेटेड रिज़ल्ट शुक्रवार को जारी हुआ। जिसमें एलन इंदौर के विनय तिवारी ने एआईआर 96 हासिल की। विनय के पिता गांव रोन्दिया, तहसील बेरसिया, ज़िला विदिशा में खेतीहर किसान हैं। उनके पास विनय को पढ़ाने की उचित व्यवस्था नहीं थी।उन्होंने उसे पढ़ने विदिशा में शिवकान्त तिवारी (मामा) के पास भेज दिया। मामा ने नर्सरी से दसवीं क्लास तक पढ़ाया।

विनय के गांव में अभी तक एक भी डॉक्टर नहीं है। इसका प्रभाव उसने बचपन से ही महसूस किया और अपने मामा को बताया की

मुझे डॉक्टर बनना है।इसके बाद आईएएस बनना है, क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है जो उसे पूरी करना है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद विनय ने 10वीं सीबीएसई में 96.6 प्रतिशत अर्जित किए। फिर मामा ने नीट परीक्षा के लिए विनय का एडमिशन एलन इंदौर में करा दिया।एलन इंदौर के सेंटर हेड कमल शर्मा ने बताया विनय ने एलन के कोहिनूर हॉस्टल में रहते हुए दो साल कड़ी मेहनत की, तथा अपने पहले ही प्रयास में फ्रेशर सेलेक्ट हुआ। विनय ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए यानी 180 प्रश्नों में से मात्र एक प्रश्न ग़लत किया।

विनय की पहले जारी रिजल्ट में एआईआर 201 थी जो बाद में पहले करेक्शन के बाद एआईआर 196 हुई और अब अपडेटेड रिज़ल्ट में एआईआर 96 व ईडब्ल्यूएस रैंक 10 है। जिसके माध्यम से देश के सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज एआईआईएमएस देहली में एडमिशन मिल जाएगा। जिस गांव से आज़ादी के बाद से आज तक एक भी व्यक्ति डॉक्टर ना बना हो।

इंदौर में स्मार्ट मीटर परियोजना की समीक्षा बैठक

स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने, लॉस घटाने, उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने में कारगर

इंदौर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब तक इंदौर शहर में करीब तीन लाख और कंपनी क्षेत्र में लगभग सात लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इन स्मार्ट मीटरों से चोरी व लाइन लॉस घटाने में मदद मिली है। उपभोक्ता सेवाओं में भी व्यापक रूप से बढ़ोत्तरी हुई है। यह बातें कंपनी के एमडी अमित तोमर ने पोलोग्राउंड स्थित मुख्यालय में स्मार्ट मीटर परियोजना की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरों से बिलिंग, रीडिंग संबंधित विवाद एवं असंतुष्टि की शिकायतें काफी कम हुई है। यह मीटर पहली तारीख को रीडिंग ले लेते है। बिल समय पर बनता है, बिल त्रुटिरहित बनने से अधिकाधिक उपभोक्ताओं में समय पर बिल भरने की भावना का भी संचार हुआ है। तोमर ने आगे कहा कि यह मीटर समय पर रीडिंग लेते है, इसी कारण प्रत्येक पात्र घरेलू उपभोक्ता को अटल गृह ज्योति योजना की सब्सिडी दी जा रही है, इसी तरह गैर घरेलू उपभोक्ता को पॉवर फैक्टर की लाभ भी समय पर दिया जा रहा है। तोमर ने आगे कहा कि जहां भी अभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है, वहां सर्विस केबल ठीक से लगी हो, मीटर सही लगे, सीलिंग सही की जाए। इनसे सुरक्षा एवं मीटर संचालन कार्य ठीक प्रकार से होगा, गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी।

न्याय नगर में 7 अगस्त को रिमूवल की बड़ी कार्रवाई

इंदौर (एजेंसी)। न्याय नगर संस्था की कृष्ण बाग कॉलोनी में शुक्रवार को 15 मकानों को तोड़े जाने के बाद अब 7 अगस्त को प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में बचे 60 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जाएगा। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को 10-12 मकानों को तोड़ा गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच दो बार आदेश जारी कर चुकी है। प्रशासन द्वारा रहवासियों को पहले ही तीन माह का समय दे चुका है। इसके बाद कोर्ट ने एक माह तक का समय और दिया था। इसकी अवधि 8 अगस्त को खत्म हो रही है। रहवासियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। इसमें 6 अगस्त को सुनवाई है। अगर इसमें रहवासियों को राहत नहीं मिलती है तो 7 अगस्त को रिमूवल की बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब

मृतक के परिजन ने मुआवजे को लेकर कोर्ट में लगाई थी याचिका

इंदौर (एजेंसी)। बावड़ी हादसे में इंदौर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से जवाब मांगा है। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में कम मुआवजा मिला था। इस पर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। दरअसल, बावड़ी हादसे में इंदर जानकी (40) की मौत हो गई थी। शासन ने मुआवजे के रूप में मृतक के परिजनों को सात लाख रुपए दिए थे। इसके बाद मृतक के पिता नारायण जानकी द्वारा परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार से आर्थिक मदद के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें बताया कि घर में कमाई करने वाला अब कोई नहीं है। मृतक के दो बच्चे हैं। बच्चों की स्कूल फीस देने की भी मांग की गई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 45 दिनों में जवाब पेश करने के लिए कहा है। बता दें 30 मार्च 2023 को स्नेहनगर (पटेल नगर) में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर स्थित बावड़ी में स्लैब धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी।

इंदौर में आयोजित हुए बजट पर सेमिनार

सीए ब्रांच के विश्लेषण सत्र में एक्सपर्ट्स ने बताया नफा नुकसान का गणित

इंदौर (एजेंसी)। बजट में आए इनकम टैक्स और जीएसटी में बदलावों पर इंदौर सीए शाखा और टैक्स प्रैक्टिशनर एसो. ने सेमिनार का आयोजन किया। इसमें 500 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपस्थित थे। मुख्य वक्ता सीए मनीष डफरिया ने कहा, बजट में 99 बदलाव इनकम टैक्स में हुए हैं। सरकार 6 माह में इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन की बात कर रही है, परंतु एक्ट जस का तस है। इस बार नई टैक्स स्लैब तो बजट में आ गई, परंतु धारा 87-ए में टैक्स से मिलने वाली छूट में चेंज रह गया। इस बजट में सरकार ने वेतनभोगी करदाताओं को ऊंट के मुंह में जीरे के रूप में स्टैंडर्ड डिडक्शन नई स्कीम में 25 हजार से बढ़ा दिया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो परिवर्तन किए

उसकी जरूरत लंबे समय से थी। इस बार स्पष्ट कर दिया है कि रहवासी मकान को किराए से देकर होने वाली आय को व्यापार से होने वाली आय नहीं माना जा सकता। शेयर्स एवं म्यूचुअल फंड के विक्रय पर एसटीटी लगने के बाद भी टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है।

इनकम टैक्स में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई

सीए कीर्ति जोशी ने जीएसटी में आए बदलावों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बजट में नॉन फ्रॉड केस में निकाले गए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है। इंदौर ब्रांच शाखा के अध्यक्ष सीए अतिशय खासगीवाला ने कहा कि पिछले वर्ष 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जिसमें से दो तिहाई से अधिक पर्सनल टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रेजीम को चुना। इस बजट में यह उम्मीद थी की बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाएगा या होम लोन की छूट की सीमा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई।

सरकार लाई आर 1-ए फॉर्म, लेकिन समस्या हल नहीं- फॉर्म जीएसटी आर-1 से छूटी हुई जानकारी भरने का विकल्प, टैक्स भरने की आखिरी तारीख तक फिर से भरने का मौका दिया जा रहा है। किसी करदाता ने बिक्री जीएसटी-आर-1 में नहीं दिखाई हो तो वो आर-1-ए में दिखा सकता है। कुछ गलत भर दिया है तो उसे भी ठीक कर सकता है।

इंदौर-अयोध्या के बीच अब तक नहीं शुरू हो सकी बस

एआईसीटीएसएल अब बदलाव के साथ जारी करेगा टेंडर

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर से अयोध्या के बीच बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। एआईसीटीएसएल ने इंदौर से अयोध्या के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए दिसंबर-जनवरी माह में ऑनलाइन टेंडर जारी किए थे। इसके साथ ही एआईसीटीएसएल द्वारा इंदौर से इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसें चलाने के लिए पहले भी दो बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन ऑपरेटर्स न मिल पाने के कारण बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। जिसके बाद अब एक बार फिर एआईसीटीएसएल नया प्रस्ताव बनाकर बनाकर टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। एआईसीटीएसएल सूत्रों ने बताया कि इंदौर से अयोध्या सहित 17

अन्य शहरों के बीच बस का संचालन करने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर प्रबंधन ने दोबारा टेंडर शर्तों में कुछ बदलाव के साथ टेंडर तैयार किए हैं। जिनको जल्द ही ऑनलाइन जारी किया जाएगा। प्रबंधन की अब अयोध्या के साथ 17 शहरों के लिए 42 बसें चलाने की योजना है। एआईसीटीएसल से मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन इंदौर से अयोध्या के लिए 2 बस, वाराणसी के लिए 2 बस, दिल्ली के लिए 2 बस, मुंबई के लिए 4 बस, अहमदाबाद के लिए 4 बस, पुणे के लिए 4 बस, नीमच के लिए 4 बस, राजकोट के लिए 2 बस, रायपुर के लिए 2 बस, कानपुर के लिए 2 बस, जयपुर के लिए 2 बस, ग्वालियर के लिए 2 बस, कोटा के लिए 2 बस, उदयपुर के लिए 2 बस, बांसवाड़ा के लिए 2 बस, भुसावल के लिए 2 बस और शहडोल के लिए 2 बस का संचालन करने के लिए टेंडर जारी करेगा।

दूरी के हिसाब से तय होगा किराया और सीटें

एआईसीटीएसएल अधिकारियों ने बताया कि 17 शहरों के लिए कुल 42 बसें चलाई जाएंगी। यह बसे गंतव्य के पहले सिर्फ कुछ ही स्थानों पर रुकेंगी, जिससे यह गंतव्य तक पहुंचने में अपेक्षाकृत कम समय लेंगी। बसे वातानुकूलित (एसी) होने के साथ ही अत्याधुनिक होंगी। बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस, कैमरे, पैनिक बटन, फायर अलार्म जैसी कई सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही ये बसे काफी आरामदायक भी होंगी। बसों में रूट की दूरी के हिसाब से सीटिंग भी होगी।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, रविवार 28 जुलाई , 2024

संपादकीय

खनिज पर हक किसका केंद्र या राज्य सरकार का

राज्य सरकारों में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है, उस अनुपात में उन्हें बजटीय आबंटन नहीं मिलता। जबसे जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपने हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीजों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खनिजों के स्वामित्व का प्रश्न भी उनमें एक है। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया, तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। वे उनका पट्टा देने को स्वतंत्र हैं। इसके लिए किए गए करार की एवज में वे जो शुल्क प्राप्त करती हैं, उसे कर नहीं कहा जा सकता। वह रायल्टी की श्रेणी में आता है। रायल्टी को कर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले से खासकर ओड़ीशा और झारखंड को बड़ी राहत मिली है। हालांकि करीब पैंतीस वर्ष पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाया था कि केंद्र सरकार उससे उपकर नहीं वसूल सकती। तब अदालत ने कहा था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मगर दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने करीब बीस वर्ष पहले उस फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला छापे की गलती से भ्रामक हो गया था। केंद्र को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। अब नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर बहुमत से फैसला दिया है कि

खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार है। दरअसल, यह मामला इसलिए उलझा हुआ था कि संविधान में केंद्र को खदानों के आबंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। मगर जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए केंद्र सरकार खनिजों पर कर लगाने लगी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राज्य सरकार की संपदा हैं, इसलिए वह उसके पट्टे की कीमत तय कर सकती है। अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार कर वसूलने लगेगी, तो राज्यों को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें केंद्र द्वारा वसूला गया कर वापस दिलाने की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इसका निपटारा किस प्रकार होगा, देखने की बात है। 'खनिजों पर लगने वाला टैक्स नहीं माना जा सकता रॉयल्टीज', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया झटका, जानें राज्यों को क्या होगा फायदा राज्य सरकारों में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है, उस अनुपात में उन्हें बजटीय आबंटन नहीं मिलता। जबसे जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपने हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। इस तरह कई राज्यों में विकास परियोजनाएं ठहर जाती हैं। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद उन राज्यों को अपना राजस्व जुटाने में काफी मदद मिलेगी, जहां खनिज पदार्थों की बहुलता है। ओड़ीशा, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की खदानें हैं, मगर वे उनका पूरा लाभ नहीं ले पातीं, क्योंकि उन पर अभी तक केंद्र सरकार भी अपना हक जताती आ रही थी। यह ठीक है कि राज्यों से प्राप्त राजस्व से ही केंद्र सरकार पूरे देश की विकास परियोजनाओं में संतुलन कायम करती है, मगर उनकी आय के निजी स्रोत नहीं होंगे, तो वे केंद्र के सामने हर वक्त याचक की मुद्रा में ही होंगी। इसलिए खनिज संपन्न राज्यों में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है।

सड़क पर वाहन चालकों की जानलेवा रफ्तार

सड़क हादसों में ज्यादातर की वजह कुछ वाहन चालकों की ऐसी लापरवाही होती है, जिसमें इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अन्य व्यक्ति के जीवन का भी कोई मोल है। यह सही है कि बहुत सारे लोग सड़क पर सावधानी और जिम्मेदारी से वाहन चलाते हैं और इस तरह वे सड़क पर सफर कर रहे अन्य लोगों के साथ-साथ अपनी जिंदगी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मगर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो शायद यह मान कर चलते हैं कि उनके लिए दूसरों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार की रात तीन लोग सड़क के किनारे सो रहे थे, तब एक वाहन चालक उन तीनों को बुरी तरह कुचल कर फरार हो गया। उनमें से दो की मौत हो गई, तीसरा बुरी तरह घायल हो गया। इतना तय है कि हादसे के शिकार लोगों के पास शायद फिलहाल वही ठिकाना था और वे सड़क किनारे की किसी जगह को सुरक्षित मान कर वहां सो रहे थे। अगर किसी बेलगाम वाहन ने उन्हें कुचल डाला, तो इसे चालक की आपराधिक लापरवाही ही कहा जाना चाहिए। निश्चित रूप से सड़कों के किनारे आसपास की जगहें सोने के लिए नहीं होती हैं और वहां हमेशा जोखिम बना रहता है। मगर एक समस्या यह है कि महानगरों में रोजी-रोटी की तलाश में आए किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे का अभाव या किसी मजबूरी की वजह से रहने का ठिकाना नहीं है, तो उसे कई बार सड़कों के किनारे या फुटपाथों पर सोना पड़ जाता है। सरकार की ओर से घोषित तौर पर रैन बसेरे जैसी व्यवस्था है, लेकिन या तो वह बेघर लोगों की संख्या के लिहाज से अपर्याप्त है या फिर इस कदर कुव्यवस्था का शिकार है कि वहां ज्यादातर लोग नहीं जाना चाहते। अक्सर ऐसे हादसों की खबरें आती रहती हैं, जिनमें किसी वाहन चालक की लापरवाही की वजह से फुटपाथ पर सो रहे लोगों की कुचल कर मौत हो गई। यह समझना मुश्किल है कि इस तरह वाहन चला रहे किसी व्यक्ति को कितनी हड़बड़ी और कैसी बेफिक्री होती है कि उसे सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जिंदगी और हालात की अहमियत समझना जरूरी नहीं लगता।

आज का कार्टून

रोजगार और विकास का बजट

-अवधेश कुमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024 -25 के बजट पर आम प्रतिक्रियाएं अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं। हालांकि सामान्य दृष्टि से भी देखें तो यह बजट ऐसा है जिसमें विपक्ष को तीखी आलोचनाओं के लिए ठोस आधार प्राप्त नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के पूर्व से लेकर अभी तक विपक्ष ने इस सरकार पर युवाओं, किसानों ,गरीबों को नजरअंदाज करने तथा बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस बजट का आरंभ ही युवाओं और रोजगार सृजन से हुआ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके संदर्भ में अंतरिम बजट में काफी प्रावधान किए गए थे। यह बजट उसी का विस्तारित रूप है। बजट को समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है।

यह एक साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने, स्वरोजगार सृजन पर बल देने, भारत की विरासत तीर्थ और पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा सबके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विस्तार पर फोकस करने वाला बजट है। यह बजट फिर एक बार बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का भारत को लेकर सपना क्या हैं। उन्होंने पहले भी अपने भाषणों तथा पिछले सारे बजटों में वैसे भारत की रूप-रेखा प्रस्तुत की है जो वर्तमान अर्थव्यवस्था के मानदंड में विश्व के शीर्ष देशों की कतार में हो, जहां लोगों को जीविकोपार्जन के साधन हों, स्किल से भरे युवाओं तथा समाज का हर वर्ग युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग व कारोबारी सबके बीच संतुलन भी हो। किंतु इन सबके साथ भारत अपने अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति और विरासत की मूल पहचान के साथ विकसित भारत बने। इस बजट में इन सपनों का समग्रता से समावेश है लेकिन इसका मुख्य यू.एस.पी. रोजगार है।

आप देखेंगे कि 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां-जहां सबसे ज्यादा फोक्स करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पी.एम. मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 3000 नए आई.टी.आई., 7 आई.आई.टी., 16 आई.आई.आई.टी., 7 आई.आई.एम., 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। वस्तुतः नैशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख ही है। नौकरी की संख्या बढने के बावजूद काफी युवा वंचित हैं तो इसका कारण स्किल के मापदंड पर खरा नहीं उतरना है। तक हम स्किल के मापदंडओं पर काफी पीछे हैं। इस दृष्टि से बजट में युवाओं की इंटर्नशिप की एक ऐसी विशिष्ट योजना है

जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं गया था। एक करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में शीर्ष-500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना इस बजट का प्रमुख आकर्षण है। सीधे काम करते हुए स्किल विकास की ऐसी योजना पहले नहीं आई थी। इसमें इंटर्नशिप करने आए युवाओं तथा कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं दिया गया है। युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपए का भत्ता तथा एकमुश्त मदद के रूप में 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करनी होगी।

कॉरपोरेट अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि खर्च करते हैं। उन्हें उसी में से प्रदान करना है। इस तरह यह पूरी तरह व्यावहारिक है। कल्पना करिए अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में भारत कैसे स्किल वाले युवाओं का देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा भी विशिष्ट है। इस तरह की कई घोषणाएं बताती है कि कितनी गहराई से विचार किया गया है। रोजगार अपने आप में अर्थव्यवस्था में टापू नहीं हो सकता। संपूर्ण विकास और उसमें स्थिरता सतत स्थाई रोजगार पैदा होने का आधार होता है। स्थायी रोजगार स्वयं में पैदा होता रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि रोजगार सृजन में कृषि का हिस्सा अभी भी 45 प्रतिशत है। यानी कृषि को ठीक से संभाला जाए तो यह विकास के साथ-साथ बेहतर रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का दीर्घकालिक क्षेत्र साबित होगा।

कृषि और उससे जुड़े सैक्टर के लिए 1लाख 52 हजार करोड़ दिया गया है जो पिछले साल 1 लाख 25 हजार करोड़ से 21.6 प्रतिशत ज्यादा है। 400 जिलों में फसलों के सर्वे से वहां किसानों के लिए कौन-सा फसल उपयुक्त और लाभदायक होगी उसके प्रचार और प्रोत्साहन पर काम होगा। 32 फसलों की 109 नई किस्में आएंगी। बजट के सारे प्रस्तावों पर यहां विचार करना संभव नहीं। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकर लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए देश के समग्र विकास के लिए दूरगामी सोच और योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। बिहार और आंध्रप्रदेश के पैकेज को राजनीतिक व्यवस्था में बांध दिया गया है। बिहार में गया, बोधगया राजगीर और नालंदा का विकास क्या केंद्र का दायित्व नहीं है? इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने स्वयं को अपनी पहचान के साथ विकसित देश के रूप में खड़ा करने की दिशा में गति बना दी है। गठबंधन सरकार से नीतियों पर प्रभाव नहीं पड़ा तो यह अच्छा संकेत है।

अकाली संकट : पांच सिंह साहिबानों के लिए परीक्षा की घड़ी

पंजाब में 10 साल तक लगातार शासन करने के बाद अकाली दल बादल पिछले 2 बार से सत्ता से बाहर है और अब लोकसभा चुनाव में करारी हार ने अकाली दल को विभाजन के कगार पर खड़ा कर दिया है। अकाली दल की लड़ाई अब अकाल तख्त साहिब तक पहुंच गई है। पंजाब में 10 साल तक लगातार शासन करने के बाद अकाली दल बादल पिछले 2 बार से सत्ता से बाहर है और अब लोकसभा चुनाव में करारी हार ने अकाली दल को विभाजन के कगार पर खड़ा कर दिया है। अकाली दल की लड़ाई अब अकाल तख्त साहिब तक पहुंच गई है। हालांकि ऐसी स्थिति पहले भी कई बार बन चुकी है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है क्योंकि इस बार अकाली दल इतनी कमजोर स्थिति में है जहां पहले कभी नहीं पहुंचा और इस बार बड़े विद्रोही नेताओं की संख्या कब्जा करने वाले गुट से अधिक है जबकि पहले आपसी लड़ाइयों के दौरान, कब्जा करने वाला गुट आमतौर पर सरकार चला रहा था और बड़े नेताओं का समर्थन भी कब्जा करने वाले गुट के साथ अधिक था। अकाली दल में फूट का इतिहास बहुत पुराना है। अगर 1966 में भाषा के आधार पर पंजाबी सूबे के अस्तित्व में आने की बात करें तो पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव के दौरान अकाली दल 2 गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व संत फतेह सिंह और दूसरे गुट का नेतृत्व मास्टर तारा सिंह ने किया। विभाजन के इतिहास में न जाकर, आज हम केवल विभाजन के उन मामलों के बारे में बात करेंगे जिनमें अकाल तख्त को हस्तक्षेप करना पड़ा था या अकाली नेताओं द्वारा अकाल तख्त से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। 1984 में आप्रेशन ब्ल्यू स्टार के बाद केंद्र सरकार ने अकाली दल के नेतृत्व जिनमें जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहरा, प्रकाश सिंह बादल, जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी और संत हरचंद सिंह लौंगोवाल को जेल भेज दिया तो अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार साहिब ने पार्टी चलाने के लिए पांच प्यारे नियुक्त किए। 1988 में उस समय के अकाल तख्त के जत्थेदार रागी दर्शन सिंह ने उस समय अहम भूमिका अदा की जब उदारवादी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच अलगाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 1990 के शुरूआती दौर में कार्यवाहक जत्थेदार प्रो. मंजीत सिंह अकाली दल को एकजुट करने की कोशिश में थे और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया मगर स. प्रकाश सिंह बादल इस निर्णय से अलग ही रहे। 1999 में अकाली नेताओं गुरचरण सिंह टोहरा और प्रकाश सिंह बादल के झगड़े के समय अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार भाई रणजीत सिंह ने भी समझौता करवाने का प्रयास किया मगर उन्हें जत्थेदारी से हटा दिया गया। अकाली दल की लड़ाई का अकाल तख्त पर पहुंचने का यह पांचवां मौका है और इस बार अकाल तख्त के जत्थेदार तथा अन्य 4 सिंह साहिबान के लिए बागी अकाली नेताओं की ओर से दी गई माफी की चिट्ठी पर निर्णय करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक ओर तो सिंह साहिबान इन अकाली गटों में फैसला करवाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर सर्बजीत सिंह जो अभी सांसद बने हैं, ने फरीदकोट में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अमृतपाल सिंह एम.पी. के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने की घोषणा कर डाली। इस बात ने अकाल तख्त के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। इसके अलावा कई अन्य अकाली गुट भी हैं जिनमें मुख्य तौर पर भाई जसबीर सिंह रोडे और पूर्व जत्थेदार भाई रणजीत सिंह सुखबीर सिंह बादल का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अकाल तख्त केवल अकाली दल बादल की एकता करवाने के लिए या इसके नेताओं की ओर से की गई गलतियों का निर्णय ही करेगा? बागी अकाली नेताओं ने खुद को अकाल तख्त के समक्ष पेश कर दिया और सुखबीर सिंह बादल को भी अकाल तख्त पर पेश होने की मांग की जिसे मानते हुए अकाल तख्त के जत्थेदार ने सुखबीर सिंह बादल को भी 15 दिनों में अकाल तख्त साहिब पर पेश होने के लिए कहा है और सुखबीर बुधवार को अपने साथियों सहित अकाल तख्त पर पेश होकर स्पष्टीकरण दे आए हैं।

नशों से समाप्त होती आज की जवानी

-अविनाश राय खन्ना(पूर्व सांसद)

पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर कंटीली तारें कई दशकों से जीरो लाइन पर बनने के स्थान पर भारत की सीमाओं के अंदर बांधी गई हैं, कहीं-कहीं पर तो ये तारें जीरो लाइन से एक किलोमीटर से भी अधिक भारत की तरफ देखी जाती हैं। यदि इन तारों को जीरो लाइन पर ही लगा दिया जाए तो नशीले पदार्थों की तस्करी भी रोकी जा सकती है। पाकिस्तान से आने वाला नशा एक और मायने में बड़ा भयंकर है जिसे 'चिट्टा' कहा जाता है। यह 'चिट्टा' वास्तव में एक सिंथैटिक नशा है जो अत्यन्त हानिकारक रासायनिक पदार्थों से बनता है। इसका नशा शरीर के अंदर सारे तंत्रों को तीव्र गति से हानि पहुंचाता है। इन्हीं कारणों से पंजाब का नशा सारी दुनिया में फैले नशे की समस्या से अधिक गम्भीर है। नशे के कारण व्यक्ति सबसे पहले तो अपने घर का ही धन बर्बाद करता है। धन पर रोक लगती है तो वह सबसे पहले अपने घर में ही चोरियां शुरू करता है। इसके बाद नशे का प्रभाव समाज को भी झेलना पड़ता है क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति समाज में भी अपराध का खिलौना जल्दी बन जाता है। नशे के कारण व्यक्ति किसी व्यापार या नौकरी के लायक भी नहीं रहता। यह बेरोजगारी और अपराध तीसरे स्तर पर सरकार के लिए भी एक समस्या बन जाते हैं। पुलिस, प्रशासन, समाजसेवा आदि जैसे सरकारी विभागों को सामूहिक रूप से एक नीति का निर्माण करना चाहिए कि जितना संघर्ष उन्हें नशा करने वाले व्यक्ति के अपराधों के प्रबंधन में करना पड़ता है, उससे कम प्रयास से

नशे के वितरण प्रणाली को ही क्यों न समाप्त किया जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर एक मजबूत और लक्ष्यबद्ध इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। नशे की आदत डालने के बाद हमारे समाज को जितना संघर्ष करना पड़ता है, यदि नशे के विरुद्ध चेतावनी देने के प्रयास छोटी अवस्था के बच्चों में ही पूरी चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रारम्भ कर दिए जाएं तो इसके बड़े सुंदर परिणाम निकल सकते हैं। इसके लिए स्कूलों के अध्यापकों और धार्मिक स्थलों के विद्वानों को विशेष प्रयास प्रारम्भ करने चाहिएं। उससे भी पहले ये प्रयास घरों में ही अपने बच्चों की चेतना जागृत करने के लिए माता-पिता तथा घर के अन्य वृद्धजनों के द्वारा प्रारंभ कर दिए जाने चाहिएं। सामाजिक संस्थाएं घर-घर अभियान चलाकर छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से तथा वार्तालाप के माध्यम से छोटे और युवा होते बच्चों की नशा के विरुद्ध चेतना जागृत करें। मैं स्वयं जब भी किसी शिक्षण संस्थान में जाता हूं तो अपने उद्बोधन में पर्यावरण सुरक्षा, माता-पिता की सेवा और नैतिकता की अनेकों बातों के बीच नशों के विरुद्ध अवश्य ही चर्चा करता हूं और बच्चों से भविष्य में नशा न करने का संकल्प करवाता हूं। बच्चों पर स्कूलों और धर्मस्थलों से मिली शिक्षा की गहरी छाप पड़ती है। इसलिए हम सबको मिलकर नशों के विरुद्ध चेतना को अपने बच्चों की शिक्षा का अंग बना देना चाहिए, नहीं तो इन नशों के कारण हमारे समाज की जवानी पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। स्कूलों में बच्चों को लेकर नशे की हानियों के संबंध में डिबेट करवाई जाए, चित्र प्रतियोगिता करवाई जाए, बच्चों के घरों के अनुभवों पर उनके विचार सुने जाएं, बच्चों की गली-गली रैलियां निकाली जाएं और बच्चों को ऐसे अभियानों में खुलकर प्रोत्साहित किया जाए तो आज दिखाई देने में यह छोटा-सा प्रयास कुछ ही वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदल सकता है।

बजट में आई नई योजना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करें कन्वर्ट....

नईदिल्ली, एजेंसी। देश में कालेधन को सफेद करने के लिए मोदी सरकार ने बजट में एक नई योजना पेश की है। इस योजना के मुताबिक, यदि आपके पास छापेमारी में पकड़े जाने की स्थिति में अघोषित धन है तो आप इस पर सरकार को 60 प्रतिशत टैक्स देकर इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते है। गौरतलब है कि देश में आयकर की अधिकतम दर 30 प्रतिशत है लेकिन यदि आपके पास काला धन पकड़ा जाता है तो आपको न सिर्फ पकड़े गए धन के ऊपर बनता टैक्स देना पड़ेगा बल्कि इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही कई मामलों में काले धन के आरोपियो को जेल की भी सजा हो जाती है लेकिन सरकार ने इस नई य़ोजना के तहत यदि आप अपनी छुपाई गई इनकम पर सरकार को 60 फीसदी टैक्स दे देते है तो आपका मामला पहली ही सुनवाई में खत्म हो जाएगा। इस पर आपको कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। बजट में की गई इस घोषणा के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उम्मीद है कि देश में बहुत सारे लोग इस नई योजना का फायदा उठाएंगा क्योंकि आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली छापेमारी में पकड़े जाने वाले धन को लेकर लंबी कानूनी कार्रवाई चलती है जिसके कारण काला धन रखने वाले लोगों के अलावा सरकार के अफसरों का भी समय खराब होता है।

सीबीडीटी के चेयरमेन रवि अग्रवाल ने कहा कि आम तौर आयकर विभाग द्वारा तलाशी ली जाने के बाद अघोषित आय के साक्ष्यों की जांच करते है।

इसके बाद नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू होता है और सालों तक सुनवाई चलती रहती है। अब नई योजना में यदि करदाता इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा किए गए विश्लेषण को मान लेता है तो इस मामले में एक की ही सुनवाई होगी और 60 प्रतिशत टैक्स देने पर मामला खत्म भी हो जाएगा। लेकिन करदाता आकलन से ज्यादा आघोषित आय स्वीकार करता है तो अतिरिक्त रकम पर 50 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकता है मगर अब नई योजना में पिछ्ले 6 सालों के मामलों का एक ही बार में निपटारा हो जाएगा।

नई योजना का मुख्य उद्देशय

नई योजना का मुख्य उद्देशय तलाशी के आकलन को अंतरिम रूप देना है। तलाशी की जांच में तालमेल करना और इसके तहत होने वाली कार्रवाईयों को खत्म करना है। पिछ्ले 6 साल के एक ब्लॉक से संबंधित कुल आय पर आयकर कानून की धारा 113 में बताई गई दरों के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा और पिछ्ले वर्षों की आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट की बढ़ी मुश्किलें, सेबी ने पुराने मामले को फिर से खोला

नईदिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड कंपनी एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाजार नियामक सेबी ने न सिर्फ एक पुराने मामले को फिर से खोल दिया है, बल्कि इसके साथ ही कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सेबी ने पुराने केस को फिर से खोला

पहले भी इस मामले में एक आदेश जारी किया जा चुका था लेकिन सेबी अब मानती है कि पुराने आदेश में एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हक को बहाल करने का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। नियामक ने उस आदेश की गलती को सुधारने के लिए मामले को दोबारा खोला है और कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी का यह एक्शन एचएसबीसी समूह द्वारा एलएंडटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है। एचएसबीसी ने पिछ्ले साल मई में एलएंडटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया था और अक्टूबर 2023 में इसे अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचएसबीसी एएमसी के साथ मर्ज कर दिया था। वर्तमान नियमों के अनुसार, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को निवेश निर्णयों से जुड़े सभी रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है, जिसमें निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार डेटा, तथ्य और राय शामिल होते हैं। एचएसबीसी एएमसी के एलएंडटी एएमसी के अधिग्रहण के मामले में इसी प्रावधान से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं।

पिछले साल समाप्त हुआ था मामला

सेबी ने इस मामले में 6 नवंबर 2023 को नया शो कॉज नोटिस जारी किया था। इससे पहले, 23 अगस्त 2023 को सेबी ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मामला समाप्त करते हुए कहा था कि आरोप साबित नहीं हुए थे। हालांकि, अब उस आदेश को पलट दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।

संक्षिप्त समाचार

यूपी की तरह विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे, विनिर्माण व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

नईदिल्ली, एजेंसी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया, ऐसे दो औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जा रहे हैं।वहीं, आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि बजट में 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है।इससे देश में इन शहरों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी।

आठ शहर पहले से ही विकास चरण में

सचिव ने कहा, आठऔद्योगिक शहरों में से गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के ऑरिक, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम में इनकी बसावट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा चुका है। भूखंड आवंटन का काम चल रहा है। चार अन्य शहरों में भी सड़क संपर्क, पानी व बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है।

कैबिनेट से करेंगे संपर्क

सिंह ने कहा, इन शहरों के लिए योजनाएं तैयार हैं और जमीन राज्य सरकारों के पास है। हमें बस इसके लिए गठित विशेष उद्देश्य वाली इकाइयों (एसपीवी) को इक्विटी मंजूरी देनी है। डीपीआईआईटी नए शहरों के लिए कैबिनेट से संपर्क करेगा। फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा, भारत का चुनाव बाद का बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गठबंधन में शामिल दलों की मांग के बावजूद नई सरकार राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर टिकी हुई है। फिच ने कहा, हमारा मानना है कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, क्योंकि 2024-25 में सरकार का अनुमान बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि 10.5 फीसदी रहने का है, जो हमारे मौजूदा पूर्वानुमान से थोड़ा कम है।

भारत में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप्स ; सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री की ओर से शुक्रवार को सदन में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या से पता चला है कि महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कर्नाटक 15,019 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ है। उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ पांचवें स्थान पर है। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं।

बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे सुजुकी के चेयरमेन तोशिहिरो

स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर यह बोले

नईदिल्ली, एजेंसी। जापानी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने शुक्रवार को बनासकांठा के बनास डेयरी स्थित बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया। पिछले साल, जापान की सुजुकी और बनास डेयरी ने एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) के सहयोग से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था और 5 नए बायो-सीएनजी संयंत्र शुरू किए थे। बनास डेयरी के भ्रमण के दौरान जापानी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। मारुति सुजूकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। हम निकट भविष्य में वाहनों में ईंधन के रूप में बायो-सीएनजी का उपयोग चाहते हैं ताकि यह पर्यावरण को प्रभावित न करे। यह एक बहुत अच्छी पहल है।

NMC Asks Medical Colleges To Update List Of Faculty On Their Website

The National Medical Commission (NMC) has released a notification directing colleges to update the list of their faculty in each department. As per the medical body, the colleges must update the list of the faculty by July 31, 2024.

NMC noted that the list of faculty must be updated separately under each Department and should also include the names of the faculty members along with their recent photo, educational qualification, latest designation and registration number. The names reflected in the list should be in accordance with the AEBAS system of the college.

The official notification released by NMC reads, "All medical institutions must update the college website as regard the faculty in each department as follows: a. The list of faculty must be available separately under each Department (the medical superintendent, Principal, Dean, if are from any of the Departments may also be indicated here); b. The list must have name of the faculty members, his/her recent photo, educational qualification, latest designation and registration number issued by the respective State Medical Council; c. The names reflected in the list must be onboard in the AEBAS system of the college."

The notification also added that any incorrect, incomplete and/or late submission of information will attract appropriate action against the medical institutions/medical colleges concerned. The list will be updated every month and the deadline for such updating will be the last day of every month.

NMC has also notified that in some medical institutions the faculty members were marking bio-metric attendance on AEBAS using fake finger prints. Emphasising, that this is viewed seriously by the National Medical Commission, the medical body advised that all faculty members must mark their attendance personally in the AEBAS connected to the NMC at their medical college. Any incidence of impersonation would attract appropriate action, it noted.

रिलायंस-टाटा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में कुमार मंगलम बिड़ला, तैयार है 5,000 करोड़ का प्लान

नईदिल्ली, एजेंसी। कुमार मंगलम बिड़ला की अगुवाई वाला आदित्य बिड़ला ग्रुप पेंट के बाद अब जूलरी मार्केट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ग्रुप ने शुक्रवार को अपने जूलरी ब्रांड इन्द्रिय लॉन्च किया। इसमें ग्रुप का मुख्य मुकाबला टाटा ग्रुप के तनिष्क और रिलायंस के रिलायंस ज्वेल्स से है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने इस साल की शुरुआत में पेंट बिजनस में एंट्री मारी थी और वह सीमेंट बिजनस में अडानी ग्रुप को कड़ी टक्कर दे रहा है। साथ ही वह अपनी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में भी नई जान फूंकने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के रिटेल ब्रांडेड जूलरी बिजनस में उतरने से टाटा के जूलरी ब्रांड तनिष्क को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तनिष्क ने अपना पहला शोरूम 1996 में चेन्नई में खोला था।

65 अरब डॉलर के आदित्य बिड़ला ग्रुप का मुख्य जोर मेटल, सीमेंट और कपड़ा बिजनस पर रहा है। लेकिन अब वह कंज्यूमर बिजनस में तेजी से अपना

विस्तार कर रही है। ग्रुप के कुल रेवेन्यू का करीब 20 फीसदी हिस्सा इसी बिजनस से आता है। ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने इंद्रिया ब्रांड को लॉन्च करते हुए कहा कि अगले पांच साल में हमारे रेवेन्यू में कंज्यूमर बिजनस का हिस्सा बढ़ाकर 25त्न से अधिक बढ़कर लगभग 25 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। यह देश के अधिकांश अग्रणी स्टैंडअलोन कंज्यूमर बिजनसेज से बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे कई बिजनस क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार हैं जबकि नए वेंचर की प्रगति अच्छी है। हम न केवल साइज को बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने दायरे को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। साथ ही हम अपने पुराने बिजनेसेज की ताकत को अपने नए उद्यमों की ताजा ऊर्जा के साथ मिलाकर एक यूनीक ग्रोथ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप की जूलरी बिजनस में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। उसे उम्मीद है कि ब्रांड वैल्यू और रिटेल एक्सपीरिएंस के दम पर वह टॉप तीन में जगन बना सकता है।

इंद्रिया के पहले चार स्टोर शनिवार को दिल्ली, जयपुर और इंदौर में खुलेंगे। अगले छह महीनों में 10 से अधिक शहरों में प्रवेश करने की योजना है। देश में अभी जूलरी मार्केट 6.7 लाख करोड़ रुपये का है जिसके 2030 तक 11 से 13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 60त्न से अधिक अब भी असंगठित है। यही वजह है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप इस सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने जा रहा है। हालांकि बिड़ला से स्वीकार किया कि यह काम आसान नहीं है क्योंकि देश के सबसे ब्रांड के पास अब भी महज 6-7त्न हिस्सेदारी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है।

इस साल बिक जाएगा यह सरकारी बैंक

आरबीआई ने शॉर्ट लिस्ट किए गए बिडर्स, सरकार कर रही जांच-परख

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में रणनीतिक तौर पर सरकारी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम यह भी है कि ये कंपनियां शेयरधारकों के लिए वेल्थ क्रिएट करें। डिसइनवेस्टमेंट से लेकर स्ट्रैटेजिक सेल तक, अब तमाम चीजों को पब्लिक असेट मैनेजमेंट के एक बड़े दायरे में देखा जा रहा है आइडीबीआइ बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के मामले में आरबीआई शॉर्ट लिस्ट किए गए बिडर्स की जांच-परख कर रहा है और इस साल यह बिक्री पूरी हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद बैंक प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। आम बजट के बाद ह्व्व्ह्ल को दिए गए विशेष साक्षात्कार में डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय ने ये बातें कहीं।

डिसइनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी

इस बार के बजट में सरकार ने अलग से डिसइनवेस्टमेंट टारगेट नहीं रखा। इसे असेट मॉनेटाइजेशन के साथ मिलाकर अन्य प्राप्तियों के मद में डाल दिया गया है और कुल 50000 करोड़ रुपये का अनुमान दिया गया। क्या कुछ खास वजहों से विनिवेश शब्द से पोज किया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में कहा. अगर हम केवल संसाधन जुटाने की नजर से सरकारी कंपनियों को देखेंगे तो इस बात से ध्यान हट सकता है कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है।

रक्षाबंधन पर हवाई सफर करना पड़ेगा जेब पर भारी, टिकटों के दाम में हुई वृद्धि

नईदिल्ली, एजेंसी। इस साल रक्षाबंधन पर हवाई सफर करना आपके बजट पर भारी पड़ सकता है क्योंकि टिकटों के दाम 46 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। रक्षा बंधन 19 अगस्त को है लेकिन इससे पहले 15 अगस्त को भी छुट्टी है और इसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार का सप्ताहांत आएगा। लगातार लंबी छुट्टी के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है, जिससे इकॉनमी क्लासका किराया काफी ऊंचा हो गया है।

द्व×द्वद्दश के आंकड़ों के अनुसार, 14 से 20 अगस्त के बीच बेंगलूरु-कोच्चि मार्ग पर औसत किराया 3,446 रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 46.3 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह, बेंगलूरु-मुंबई मार्ग पर हवाई किराया बढ़कर 3,969 रुपए हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 37.6 प्रतिशत अधिक है।

कई विमान नहीं भर पा रहे उड़ान

विमानन उद्योग के सूत्रों ने बताया कि इंजन से संबंधित समस्याएं, आपूर्ति में अड़चनें और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि उसके बेड़े में शामिल 383 विमानों में से लगभग 70 विमानों की उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं। इस कारण उड़ानों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिससे प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, इस साल अगस्त में हर हफ्ते बेंगलूरु से कोच्चि के बीच उड़ानों की संख्या पिछले साल के समान ही है।

इस कारण बढ़ा किराया

विमानन उद्योग पर नजर रखने वाली कंपनी सिरियम के अनुसार, बेंगलूरु और मुंबई के बीच उड़ानों की संख्या इस अगस्त में पिछले साल के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम होकर 472 रह गई है। विमानन उद्योग पर शोध करने वाले और नेटवर्क थॉट्स के संस्थापक अमेय जोशी ने बताया कि लंबा सप्ताहांत और छुट्टियों की अधिकता के कारण हवाई किराया बढ़ गया है। इस साल स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षा बंधन तक की छुट्टियों के कारण देसी विमानन कंपनियों ने उड़ानों की संख्या बढ़ाने में असमर्थता जताई है, जिससे कुछ प्रमुख मार्गों पर किराया अचानक बढ़ गया है। सिरियम के अनुसार, दिल्ली और पुणे के बीच हफ्ते में 160 उड़ानें आ-जा रही हैं, जो पिछले साल के अगस्त से नहीं बढ़ी हैं। इस साल 14 से 20 अगस्त के बीच दिल्ली-पुणे मार्ग पर हवाई किराया 5,257 रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि से 22.6 प्रतिशत अधिक है।

सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय सीईओ बने सी विजयकुमार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलते हैं 84.16 करोड़ रुपये

नईदिल्ली, एजेंसी। एचसीएल टेक के सीईओ सी विजयकुमार सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय सीईओ बन गए हैं। 22 जुलाई को जारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के लिए विजयकुमार का पारिश्रमिक लगभग 84.16 करोड़ रुपये रहा, इसमें सालाना आधार पर 190.75 प्रतिशत की वृद्धि है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विजयकुमार को लगभग 1.96 मिलियन डॉलर (16.39 करोड़ रुपये) का बेसिक वेतन, 1.14 मिलियन डॉलर (9.53 करोड़ रुपये) का प्रदर्शन-लाइन बोनस, वहीं दीर्घकालिक प्रोत्साहन (एलटीआई) नकद घटक मद में लगभग 2.36 मिलियन डॉलर (19.74 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, एलटीआई आरएसयू (प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयों) मद में 4.56 मिलियन (38.15 करोड़ रुपये) का अनुलाभ मूल्य और शेष 0.04 मिलियन का भुगतान लाभ, अनुलाभ और भत्ते के रूप में दिया गया। यह कुल 10.06 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार, विजयकुमार का पारिश्रमिक एचसीएलटेक के कर्मचारियों के औसत वेतन का 707.46 गुना रहा।

शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में, सी विजयकुमार ने खुलासा किया कि कंपनी का कुल राजस्व निरंतर मुद्रा में 13.7त्न वर्ष बढ़ गया है, सेवा व्यवसाय में 15.8त्न वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा, हमारा राजस्व 100,000 करोड़ मील का पत्थर पार कर गया और हमारा कर्मचारी आधार 225,000 अंक (25,000+ प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के सेवन सहित) तक पहुंच गया, जबकि हमारे सेवा पोर्टफोलियो में डिजिटल, इंजीनियरिंग, क्लाउड, एआई और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, हमारे रणनीतिक गठजोड़ के साथ, सभी समान वजन में पंच किए गए। हमारे कार्यस्थल भी विकसित हो रहे हैं। हम वर्चुअल-फर्स्ट, हाइब्रिड वर्कप्लेस मॉडल में विश्वास करना जारी रखते हैं, जिसमें कर्मचारियों के लिए ऑफिस स्पेस का उपयोग करने और आवश्यकतानुसार रिमोट वर्किंग का लाभ उठाने के लिए लचीलापन है। हमारा दृष्टिकोण संतुलित और मापा गया है, जिसका नेतृत्व हमारे लोगों और ग्राहकों के साथ सक्रिय संवादों द्वारा किया गया है ताकि राइट-टाइम-एंडराइट-प्लेस मॉडल विकसित किया जा सके।

स्टेनोग्राफर एक अच्छा कॅरियर विकल्प

जिन युवाओं की इच्छा सरकारी नौकरी करने की है। उनके लिए स्टेनोग्राफी एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। यह 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्टेनोग्राफी करियर का एक अच्छा क्षेत्र है। स्टेनोग्राफर के पद का वेतनमान आकर्षक होता है। यह कम खर्चीला भी होता है। स्टेनोग्राफर पर कार्यालय या संस्था के गोपनीय रिकॉर्डों को संभालने का दायित्व रहता है। स्टेनोग्राफर अपने अधिकारी के प्रति विश्वनीय पद है। इस पद पर काम करना एक गरिमापूर्ण व चुनौतीपूर्ण है। अच्छी खासी तनख्वाह ऊपर से सरकारी नौकरी का रौब अलग। यही बातें हैं जो युवाओं को स्टेनोग्राफी की तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत की आवश्कता होती है।

स्टेनोग्राफी आशय होता है संक्षिप्त लेखन जिसे अंग्रेजी में शॉर्टहैंड कहा जाता है एक प्रकार की लेखन विधि होती है। हमारे देश में स्टेनोग्राफर के पद अदालतों, शासकीय कार्यालयों, मंत्रालयों, रेलवे विभागों में होते हैं। स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्कता होती है, क्योंकि इस भाषा में शब्द गति होना आवश्यक है। एक कुशल स्टेनोग्राफर बनने के लिए उस विषय की भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। देश में विभिन्न संस्थाएं स्टेनोग्राफर के कोर्स करवाए जाते हैं। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में भी स्टेनोग्राफर का एक वर्षीय कोर्स करवाया जाता है। इन संस्थानों में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षाएं भी ली जाती हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। सरकारी विभागों द्वारा विज्ञापनों में स्टेनोग्राफर की भर्तियां निकाली जाती हैं।

महत्वपूर्ण पद

हर सरकारी दफ्तर में स्टेनोग्राफर के कई पद होते हैं। स्टेनोग्राफर गरिमापूर्ण पद होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति विभागाध्यक्ष के निजी सहायक के रूप में होती है। वह कार्यालय के गोपनीय कार्य सम्भालना, डिक्टेशन कार्य और पीठासीन अधिकारी के प्रति विश्वसनीयता कायम रखने की जिम्मेदारी संभालता है। स्टेनोग्राफर पद का वेतनमान भी आकर्षक है। यह द्वितीय श्रेणी का पद है। कुशल और तीव्र गति की स्टेनोग्राफी के माध्यम से सीधे ही राजपत्रित अधिकारी का पद भी प्राप्त किया जा सकता है जिससे संसद व विधानसभा में संसदीय रिपोर्टर के पद नियुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह बहुत आकर्षक पद होता है।

जरूरी योग्यता

स्टेनोग्राफर पद के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। इस पद के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 27 वर्ष तक की आयु निर्धारित है, कुछ विभागों में अधिकतम आयु 35 वर्ष तक निर्धारित है।

भर्ती

स्टेनोग्राफर पद की भर्ती संसद, विधानसभाओं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा अन्य राजकीय उपक्रमों के माध्यम से की जाती है। इनके द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन केंद्रीय सचिवालय, शासन सचिवालय, संसद, विधानसभाओं आदि सरकारी कार्यालयों में राजकीय कर्मचारी के रूप में किया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आधुनिक कार्यालय प्रबंधन या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एमओएम के रूप में कोर्स करवाए जाते हैं। इसमें आशुलिपि के अलावा कम्प्यूटर, टंकण एवं लेखा से संबंधित कोर्स भी सम्मिलित है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में भी एक वर्षीय कोर्स करवाया जाता है।

अवसरों की भरमार है बैंकिंग क्षेत्र में

देश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने वाले सेक्टर के रूप में बैंकिंग इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के दूरदराज के इलाकों में बैंकों की नई शाखाएं खुलने तथा प्रति वर्ष लगभग 40-50 हजार बैंक कर्मियों के रिटायर होने अथवा स्वैच्छिक सेवा अवकाश लेने के कारण इस क्षेत्र में नियुक्तियां करने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। युवाओं में आज भी बैंकिंग जॉब्स का आकर्षण बना हुआ है। यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि प्रति वर्ष लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में युवा बैंकिंग चयन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बैंकों में क्लर्क और अधिकारी वर्ग की रिक्तियों को भरा जाता है।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य

देश की विशाल आबादी की ही तरह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भी व्यापक है। इसका नेटवर्क देश के लगभग साढ़े पांच लाख गाँवों को अपनी परिधि में किसी न किसी रूप में अवश्य लिए हुए है। इस विस्तृत बैंकिंग ढांचे के अंतर्गत 27 पब्लिक सेक्टर बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 44 विदेशी बैंक, 56 रीजनल रूरल बैंक, 1589 शहरी को-ऑपरेटिव बैंक, 93550 ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत गुण

ऑफिस जॉब और जीवन में स्थिरता चाहने वाले युवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर एक बेहतर और उपयुक्त करिअर ऑप्शन माना जा सकता है। इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कारूरी है कि युवा में मैथ्स के साथ एकाउंटिंग में रुचि हो। पब्लिक डीलिंग का प्रावधान होने की वजह से धैर्यवान और गुस्से से कोसों दूर रहने जैसे गुण भी काफी उपयोगी कहे जा सकते हैं।

बैंकिंग चयन परीक्षाएं

इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आई बी पी एस) द्वारा देश भर के बैंकों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा के पैटर्न आदि के बारे में आई बी पी एस की वेबसाईट से अधिकृत जानकारी हासिल की जा सकती है। इस संस्थान द्वारा आयोजित बैंकिंग परीक्षाओं में 2016-17 के दौरान लगभग 1.51 करोड़ प्रत्याशियों ने अखिल भारतीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इस तथ्य से इसकी क्षमता का सहज ही अंदाकाा हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और इससे सम्बद्ध बैंकों की रिक्तियों को भरने के लिए एस बी आई द्वारा स्वयं चयन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है।

बैंकिंग परीक्षाओं के पैटर्न

क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए बुनियादी तौर पर दो तरह के बैंकिंग एग्जाम्स का आयोजन किया जाता है। क्लेरिकल पदों के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिग, कम्प्यूटर एप्टीट्यूड, बैंकिंग/फाइनेंस इत्यादि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा में तीन स्तर पर चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। इनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं। दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन ही है।

जॉब्स के प्रकार

प्रोबेशनरी ऑफिसर (पी ओ) पर बैंक शाखा के प्रबंधन से लेकर अन्य प्रकार के समन्वयन संबंधित कार्यों का जिम्मा होता है और क्लर्क कैडर के कर्मियों द्वारा पब्लिक डीलिंग का काम मुस्तैदी से संभाला जाता है। मात्र तीन -चार वर्षों के बाद ही ये कर्मी भी पी ओ वर्ग की श्रेणी में प्रोन्नति पाकर पहुँच जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग इंडस्ट्री में विभागीय परीक्षाओं का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर समय से पूर्व प्रमोशन भी लिया जा सकता है।

बैंकिंग स्पेशियलिस्ट ऑफिसर

बैंकिंग सेक्टर में बहुसंख्यक कर्मी पी ओ और क्लेरिकल वर्ग के ही होते हैं,परन्तु इनके अलावा खास विधाओं में ट्रेंड कर्मियों की भी सभी बैंकों द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। इनमें इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी ऑफिसर(आई टी डिग्रीधारक) , एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर(एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएट), ह्युमन रिसोर्स ऑफिसर (ह्युमन रिसोर्स में एम बी ए/पर्सोनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा), लॉ ऑफिसर(एल एल बी डिग्रीधारक), मार्केटिंग ऑफिसर (मार्केटिंग की विधा में ट्रेंड), राजभाषा अधिकारी आदि का खास तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इनके पदनामों से ही इनके कार्यकलापों के महत्त्व को समझा जा सकता है।

सैलरी

बैंकिंग इंडस्ट्री की सैलरी और इनके भत्तों को एक समय में काफी आकर्षक माना जाता था लेकिन वेतनमानों में मुद्रास्फीति की बढ़ती दरों के अनुसार संशोधन नहीं होने के कारण अब इनका आकर्षण कुछ कम हुआ है। बैंक कर्मी लगातार इस दिशा में संघर्षरत हैं और उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में बैंकिंग इंडस्ट्री के वेतनमानों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाये जा सकते हैं। इसके बावजूद करिअर निर्माण और स्थाई जॉब की दृष्टि से यह क्षेत्र अभी भी युवाओं की प्राथमिकताओं में काफी ऊपर है।

स्टार्टअप नहीं बड़ी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं युवा

मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने आने वाली हालिया चुनौतियों के साथ, नौकरी चाहने वाले अब स्टार्टअप्स के बजाय बड़ी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं.

नौकरी और पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 73 प्रतिशत नौकरी चाहने वाले संगठन के साथ काम करने और करियर में आगे बढ़ने के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों को पसंद करते हैं. मंगलवार को जारी नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 27 प्रतिशत कर्मचारी अभी भी करियर के विकास के लिए स्टार्टअप पर स्विच करने पर विचार करेंगे. अपना डॉट को के संस्थापक और सीईओ निरमित पारिख ने कहा, नौकरी चाहने वालों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ भारत का नौकरी बाजार तेजी से विकसित हो रहा है. ऐसे में नौकरी चाहने वाले अब बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं.

10 हजार नौकरी चाहने वालों से पूछे गए सवाल

रिपोर्ट तैयार करने के लिए में 10,000 से अधिक नौकरी चाहने वालों और 1,000 मानव संसाधन भर्तीकर्ताओं के बयानों को शामिल किया गया है.

इसके मुताबिक नियोक्ता एक कौशल-प्रथम दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रहे हैं. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नौकरी चाहने वाले नौकरी की तलाश करते समय, स्थान, आने जाने और वर्क लाइफ बैलेंस और कंपनी की संस्कृति के साथ-साथ वेतन के साथ-साथ करियर के विकास के अवसरों को प्राथमिकता देते हैं. लगभग 73 प्रतिशत भारतीय अपनी नौकरी की खोज में करियर के विकास को प्राथमिक कारक मानते हैं. यहां तक कि वर्क लाइफ बैलेंस और लचीले काम के घंटों के महत्व को भी पार कर जाते हैं. 10 में से लगभग 9 नियोक्ताओं ने कुशल पेशेवरों के महत्व को भर्ती के लिए एक प्रमुख मानदंड के रूप में पहचाना है, हालांकि 10 में से केवल 6 नियोक्ताओं ने अपने संगठनों में अपस्किलिंग कार्यक्रमों को लागू किया है. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि नियोक्ता अब तकनीकी कौशल वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भूमिकाओं के लिए. लगभग 65 प्रतिशत पेशेवर नौकरी के साक्षात्कार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल को एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं.

स्टार्टअप्स में नौकरी जाने का डर

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं प्रासंगिक कौशल पर अधिक जोर देती हैं, 77 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने 51 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में इसके महत्व का संकेत दिया है. नौकरी के लिए बड़ी कंपनियों को चुनना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि लोग छंटनी से बचना चाहते हैं क्योंकि हाल के दिनों में स्टार्टअप्स में छंटनी तेजी से बढ़ी है. स्टार्टअप कवरेज पोर्टलने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी. उसके मुताबिक देश में अब तक 84 स्टार्टअप द्वारा 24,256 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है. कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाले स्टार्टअप्स की सूची देश में बढ़ती ही जा रही है.

कब लें कॅरियर काउंसलर की सलाह

अक्सर हम करियर काउंसलिंग का समय पहचानने में देरी कर देते हैं। जब बच्चे आगे की राह चुनने की दहलीज पर होते हैं। इसे आप हाई स्कूल (सेकेंडरी) ही मानिए, क्योंकि इसके बाद ही स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम चेंज करने का समय होता है और यही वह समय है, जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। पैरेंट्स को इसी फेज में बच्चों को करियर संबंधी गाइडेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए। इससे उसे सही सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलती है, बल्कि वह यह भी जान पाता है कि किन विषयों में वाकई उसका रूझान है। प्रोफेशनल काउंसलर मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र से बातचीत करते हैं और मनोवैज्ञानिक या साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर स्टूडेंट के टैलेंट को समझते हैं। अक्सर हम करियर काउंसलिंग का समय पहचानने में देरी कर देते हैं।

दरअसल, करियर काउंसलिंग का सही समय वह है, अगर 11वीं में सही सब्जेक्ट का चुनाव न किया, तो पूरा करियर ही यू-टर्न ले सकता है। पैरेंट्स को बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान तो देना ही चाहिए, जरूरत उन्हें यह समझने की भी है कि बच्चे की रुचि किन सब्जेक्ट्स में है और वह उनमें कैसा कर रहा है!

यह भी देखना चाहिए कि किन विषयों को पढ़ने में बच्चे का मन नहीं लगता। इसके बाद अभिभावक करियर के चुनाव में बच्चे की मदद कर सकते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैरेंट्स बच्चों के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं, यह सबको मालूम है। बच्चे का रिजल्ट भले पैरेंट्स को पता हो, लेकिन वे अक्सर उसकी पसंद को समझने में चूक जाते हैं। सिर्फ किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना उस सब्जेक्ट में बच्चे के आगे बेहतर करने की गारंटी नहीं है।पैरेंट्स के लिए इस बात को समझना जरूरी है।

इंजीनियरिंग-मेडिकल जैसे क्षेत्रों के प्रति क्रेज का ही यह नतीजा है कि मन मुताबिक पढ़ाई न कर पाने की वजह से बच्चे तनाव में घिर रहे हैं। यहीं पर बच्चों यानी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि उनके पैरेंट्स उनकी प्रतिभा को पहचान सकें और उसे अपनी पसंद के रास्ते पर बढने की इजाजत दे सकें। यह कतई जरूरी नहीं है कि साइंस में 90 या 100 फीसदी अंक लाने वाला छात्र साइंस स्ट्रीम ही पसंद करे। आज मैनेजमेंट में कई नए सब्जेक्ट आ गए हैं। हो सकता है उसकी रुचि गणित में न हो, क्योंकि 10वीं के बाद पढ़ाई का लेवल अचानक हाई हो जाता है और अगर स्टूडेंट की रुचि उसमें न हो, तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होने लगता है। काउंसलिंग में इन्हीं बातों को पैरेंट्स को समझाने की कोशिश की जाती है। नए क्षेत्रों की जानकारी काउंसलिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि काउंसलर आपको वैसे सब्जेक्ट या उभरते क्षेत्रों के बारे में भी बताते हैं, जिनसे आप अनजान होते हैं। काउंसलर आपको मार्केट ट्रेंड (देश-विदेश) के बारे में बताते हैं और इन सबसे ऊपर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चुनने में मदद करते हैं। सब्जेक्ट पसंद का होने से आप अपनी पसंद की राह पर बढ़ तो सकते हैं, लेकिन इस गलाकाट प्रतियोगिता के जमाने में अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करके ही आप दूसरों पर बढ़त ले सकते हैं। आज मैनेजमेंट में कई नए सब्जेक्ट आ गए हैं। इसी तरह लॉ का क्षेत्र बढ़ गया है। फैशन टेक्नोलॉजी का बुखार और खुमार तो है ही, खेल के क्षेत्र में हो रहे सुधार और कमाई से इस क्षेत्र में क्रिकेट के अलावा नए ऑप्शन पर भी उभरे हैं। एक काउंसलर की सलाह यहीं कारगर होती है।

पेरिस ओलंपिक का हुआ भव्य आगाज
सिंधु-शरत ने की भारतीय दल की अगुवाई

पेरिस, एजेंसी। ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रंगारंग कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और साहित्य के साथ फ्रांसीसी जुनून का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। करीब चार घंटे चली सेरेमनी में पॉप स्टार लेडी गागा, आया नाकामुरा जैसे सुपर स्टार्स ने परफॉर्म किया। बारिश ने इन परफॉर्मेंस में चार-चांद लगाया। साथ ही ओलिंपिक मशाल लिए एक मिस्टीरियस मैन आकर्षण का केंद्र रहा। शुक्रवार शाम एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ पेरिस ओलंपिक का भव्य आगाज हो चुका है। यह पहला मौका रहा, जब किसी स्टेडियम से बाहर ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रीस के प्रतिनिधियों द्वारा नदी में नावों पर राष्ट्रों की परेड में लगभग 200 देशों के एथलीटों का नेतृत्व करने के साथ हुई। भारतीय दल 84वें नंबर पर आया। इसमें पीवी सिंधु और शरत कमल तिरंगा थामे नजर आए। सबसे अंत में मेजबान फ्रांस का दल आया। खिलाड़ी सीन नदी में नाव के सहारे परेड करते नजर आए। इसमें 200 से ज्यादा देशों के करीब 7,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत के लिए पीवी सिंधु और शरत कमल ध्वजवाहक रहे। ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मौजूद रहे। पॉप स्टार लेडी गागा ने शानदार गाने की प्रस्तुति दी। परेड में भारतीय दल 84वें नंबर पर आया। इस दौरान लगभग 3 लाख दर्शक मौजूद रहे।

पेरिसपेरिस ओलंपिक्स

बलराज पंवार हीट में चौथे स्थान पर रहे, रेपेचेज दौर में लेंगे हिस्सा

पेरिस, एजेंसी। बलराज ने सात मिनट 7.11 सेकेंड का समय लिया। वह न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिनटोश (छह मिनट 55.92 सेकेंड), स्टीफानोस एनतोस्कोस (सात मिनट 1.79 सेकेंड) और अब्देलखालेक एलबाना (सात मिनट 5.06 सेकेंड) से पीछे रहे। पेरिस ओलंपिक में स्पर्धा की शुरुआत शनिवार से हो गई है और इसमें भारत के एकमात्र रोइंग खिलाड़ी बलराज पुरुष एकल स्पर्धा की पहली हीट रेस में चौथे स्थान पर रहे और अब वह रेपेचेज में हिस्सा लेंगे। प्रत्येक हीट से शीर्ष तीन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रेपेचेज के जरिए बलराज को सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बनाने का दूसरा मौका मिलेगा। 25 वर्षीय बलराज ने सात मिनट 7.11 सेकेंड का समय लिया।

वह न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिनटोश (छह मिनट 55.92 सेकेंड), स्टीफानोस एनतोस्कोस (सात मिनट 1.79 सेकेंड) और अब्देलखालेक एलबाना (सात मिनट 5.06 सेकेंड) से पीछे रहे। बलराज हालांकि सीधे क्वालीफिकेशन से चूक गए, लेकिन उनके पास रेपेचेज के जरिए दूसरा मौका मिलेगा। बलराज चीन में एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे थे और उन्होंने कोरिया में एशियाई तथा ओसियाना ओलंपिक क्वालीफिकेशन रेगाटा में कांस्य पदक जीता था।

पेरिसपेरिस ओलंपिक्स

चीन ने जीता पेरिस ओलिंपिक का पहला गोल्ड

पेरिस, एजेंसी। पेरिस 2024 पेरिस ओलिंपिक का पहला गोल्ड मेडल चीन के खाते में गया है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में चीन ने साउथ कोरिया को 16-12 से हराया। हुआंग यूटिंग और शेंग लिहाओ ने यह गोल्ड मेडल जीता।

यूटिंग 19 साल के हैं तो शेंग की उम्र सिर्फ 17 साल है। क्वालिफिकेशन राउंड में भी चीन की जोड़ी टॉप पर थी। यह जोड़ी इस इवेंट की वर्ल्ड चैंपियन भी है। साउथ कोरिया के केउम जिहयोन और हाजुन पार्क को सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

यूटिंग का दूसरा ओलिंपिक मेडल

ओलिंपिक में यह हुआंग यूटिंग का दूसरा मेडल है। 16 साल की उम्र में उन्होंने पेरिस ओलिंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था।

शेंग लिहाओ ने 17 साल की उम्र में अब लगभग सभी इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। उनके नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीन गोल्ड हैं। इसके अलावा पिछले साल एशियन गेम्स में भी उन्होंने तीन गोल्ड मेडल जीते थे।

रियो की चोट, टोक्यो की हार से सीखा, तो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड पक्का, महावीर फोगाट को है विनेश पर भरोसा

चरखी दादरी, एजेंसी। भारत की रेसलर विनेश फोगाट 50 किग्रा भारवर्ग में पेरिस ओलंपिक के लिए पदक की एक बड़ी उम्मीद हैं। यह विनेश का तीसरा ओलंपिक है, इससे पहले वह रियो और टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। विनेश फोगाट दंगल गर्ल्स गीता-बबीता फोगाट की चचेरी बहन हैं, और विनेश के ताऊ व द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट को विनेश से इस बार गोल्ड की आस है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव बलाली निवासी विनेश ने अपने कुश्ती करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश 6 अगस्त को मैट पर उतरेंगी। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि रियो ओलंपिक में विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वह चोटिल हो गई, जिसका दुख पूरे देश को हुआ। टोक्यो ओलंपिक में भी वह देश की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकीं, जहां वह मानसिक तौर पर पिछली चोट के अनुभव से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा, मेहनत के बूते विनेश ने वजन कम कर इस बार 50 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लिया है और वह गोल्ड मेडल जीतकर देश का दिल जीतेंगी।

शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय चुनौती खत्म

संदीप सिंह-इलावेनिल वालारिवन और अर्जुन बबूता-रमिता जिंदल हुए बाहर

पेरिस, एजेंसी। शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में बुरी खबर सामने आई है. इलावेनिल वलारिवन और संदीप सिंह फाइनल में जगह नहीं बना पाए और वह 12वें स्थान पर रहे. वहीं रमिता जिंदल और अर्जुन बाबुता भी छठे स्थान पर रहे. टॉप-4 टीमों ने ही मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई किया. 2 सीरीज के बाद रमिता और अर्जुन 7वें स्थान पर हैं.

वहीं इलावेनिल और संदीप मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 14वें स्थान पर हैं. याद रखें कि टॉप-4 टीमें ही मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी. शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के लिए फिलहाल अच्छी खबर नही है. रमिता और अर्जुन 9वें स्थान पर है. वहीं इलावेनिल वलारिवन और संदीप फिलहाल 14वें स्थान पर हैं. बता दें कि टॉप चार टीमें फाइनल में पहुंचेगी. इसमें से टॉप दो टीमें गोल्ड और सिल्वर के लिए लड़ेगी. वहीं बाकी दो के बीच कांस्य के लिए प्रतिस्पर्धा होगी. बलराज पंवार रोइंग के मेन्स सिंगल्स स्कल्स में अपनी हीट में चौथे नंबर पर रहे. पंवार ने 3 मिनट 31 सेकंड और 24 मिली सेकंड का समय लिया. पंवार डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सके. हालांकि लेकिन उनकी मेडल की उम्मीदें बरकरार है. उन्हें रेपचेज इवेंट के जरिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा. शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो चुके हैं. इनमें संदीप सिंह/ इलावेनिल वालारिवन और अर्जुन बबूता / रमिता जिंदल भाग ले रहे हैं. वहीं बलराज पंवार रोइंग के मेन्स सिंगल्स स्कल्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं.

राजकुमार राव भारतीय सिनेमा का भविष्य: महेश भट्ट

राजकुमार राव भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं में से एक हैं और सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता भी इस बात पर यकीन करते हैं। अभिनेता, जो 2024 के बॉक्स ऑफिस विघटनकारी के रूप में उभर रहे हैं, राव को पहले मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने भारतीय सिनेमा का भविष्य कहा था। वास्तव में, उनकी मिस्टर एंड मिसेज माही के निर्देशक शरण शर्मा ने भी सबसे बहुमुखी अभिनेता की प्रशंसा की। शर्मा ने कहा, राज सचमुच हमारे सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं। वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि वह फिल्म उद्योग के लिए एक उपहार हैं।

अभिनेता ने दो ब्लॉकबस्टर - श्रीकांत और मिस्टर एंड मिसेज माही के साथ 2024 की शानदार शुरुआत की, और अपनी आगामी फिल्म स्त्री 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक लगाने का लक्ष्य बना रहे हैं। जहां श्रीकांत और मिस्टर एंड मिसेज माही को दर्शकों ने खूब सराहा, वहीं उम्मीद है कि स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा सकती है और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरेगी।

'मैंने अपनी लाइफ में सभी एक्सपीरियंस किया' अपनी सेक्सुएलिटी पर पहली बार बोले अभय देओल- ये ऐसी चीज नहीं है जो मुझे डिफाइन करे

48 साल की उम्र में भी बॉलीवुड एक्टर अभय देओल सिंगल हैं और अब उन्होंने अपनी सेक्सुएलिटी पर बात की है। उन्होंने कहा कि इसे वो कोई लेबल नहीं देना चाहते। एक्टर ने कहा कि सेक्सुएलिटी को पहचान देने के लिए वो कोई वेस्टर्न तरीके पर विश्वास नहीं करते। वो जो हैं वो हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें डिफाइन कर सके।

हाल ही में अभय देओल ने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वह शीशे के सामने खड़े हैं और खुद को किस कर रहे हैं। इसके बाद अब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सेक्सुएलिटी को लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले को स्पेक्ट्रम की तरह देखते हैं और इसे डिफाइन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सेक्सुएलिटी की पहचान करने के वेस्टर्न तरीके को अस्वीकार करता हूं। पूर्वी नजरिया बहुत अलग है, यह हम सभी को पहचानता है। मैं अपनी सेक्सुएलिटी को परिभाषित नहीं कर सकता और यह कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह ऐसी चीज है, जिसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यह सामने वाले कंफर्ट के लिए ज्यादा है, ताकि वे आपको एक बॉक्स में रख सकें, बड़े करीने से आपको फिट कर सकें। मुझे खुद को वेस्टर्न तरीके में क्यों बयां करना है।

किसी के प्यार में पड़ी निया शर्मा ! फेस एक्सप्रेशन से किया बयां

एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों फैंटेसी-थ्रिलर-रोमांस सुहागन चुड़ैल में नजर आ रही हैं। दर्शक उनके किरदार निशिगंधा को काफी पसंद कर रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने शुक्रवार को सेट से बीटीएस (बिहाइंड द सीन) वीडियो शेयर किया। निया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुहागन चुड़ैल के सेट से बीटीएस वीडियो शेयर किया, जिसमें वह चारपाई पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उनके सामने बहुत सारी चूड़ियां रखी हैं। वह कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए और शरमाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में निया ब्लैक कलर की आउटफिट में हैं। एक्ट्रेस ने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इश्क दी बाजियां गाने को एड किया। एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो, निया शर्मा का असली नाम नेहा शर्मा है। इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला। उन्होंने साल 2010 में स्टार प्लस के शो काली-एक अग्निपरीक्षा से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन लोकप्रियता 2011 में आए सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है से मिली। इसमें उन्होंने मानवी का किरदार निभाया। यह शो 2013 में ऑफ एयर हो गया। इसके बाद, 2014 में वह अक्षय कुमार द्वारा प्रोड्यूस जी टीवी के शो जमाई राजा में नजर आईं। इसमें उन्होंने रोशनी पटेल का रोल निभाया।

दर्शकों ने शो में उनकी और रवि दुबे की जोड़ी को काफी पसंद किया था। इसके बाद निया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखा और विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में बोल्ड सींस किए। इसके अलावा, जमाई 2.0 में भी किसिंग सींस दिए।

संक्षिप्त समाचार

द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे

नईदिल्ली, एजेंसी। द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से दिल्ली से आ रहे वाहन चालकों को पटौदी या रेवाड़ी जाने में आसानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अगले साल मार्च महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, एनएचएआई का दावा है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। करीब 46 किलोमीटर लंबाई के गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-88ए और 88बी के बीच में से एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो रेवाड़ी तक जा रहा है। एनएचएआई ने सेक्टर-37डी स्थित रॉयल ग्रीन रियलिटी कोर्ट यार्ड से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई थी। इसके तहत शुक्रवार सुबह से काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत करीब 183 मीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। साल 2020 में एनएचएआई ने गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे निर्माण का ठेका एक कंपनी को दिया था। साल 2022 में यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर कई अड़चनों के चलते यह काम निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं हो सका। एनएचएआई के परियोजना अधिकारी योगेश तिलक ने कहा, द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। हाईटेंशन लाइन को स्थानांतरित करने का आग्रह एचवीपीएन से किया गया है।

17 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा युवक, किसी ने नहीं की मदद; खून बहने से जान गई

नईदिल्ली, एजेंसी। दोस्त के हमले में युवक की मौत मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बुराड़ी इलाके में हुई घटना के बाद युवक करीब 17 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल, 11 जून की शाम करीब 6.30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मुकुंदपुर रोड पर घायल हालत में युवक पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक को अस्पताल भेजा जा चुका था, जहां कुछ समय बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना का लगा। तीन दिन बाद युवक की पहचान 32 वर्षीय नीरज के तौर पर हुई। इंस्पेक्टर जसपाल के नेतृत्व में एसआई एसके झा एवं एसआई दीपक कुमार की टीम ने जांच की तो यह मामला हत्या के तौर पर सामने आया। पुलिस ने नीरज के दोस्त लव को खून से सने जूते के साथ पकड़ा तो मालूम हुआ कि लूटपाट के लिए हत्या हुई है। नीरज का परिवार संत नगर में रहता था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में दो बड़े भाई हैं। परिवार इस समय नीरज की शादी के लिए लड़की देख रहा था। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नीरज की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हुई थी। आउटर रिंग रोड से सटे मुकुंदपुर स्थित निर्माणाधीन सड़क पर सीमेंट के बड़े-बड़े ब्लॉक रखे हैं। इसी के पीछे दोनों ने साथ शराब पी। फिर नशे में धुत होकर लव नीरज से छीना झपटी करने लगा। विरोध करने पर सिर पर ईंट मारकर नीरज को घायल कर दिया और सीमेंट के ब्लॉक के पीछे फेंककर फरार हो गया। 17 घंटे बाद किसी ने उसे देखा तो पुलिस को मामले की जानकारी देने के साथ ही नीरज को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के अनुसार, अगर एक घंटे पहले भी घायल को इलाज मिल गया होता तो उसकी जान बच सकती थी।

काम किए बिना ही पैसे दिए, पीडब्ल्यूडी में हुआ 200 करोड़ का घोटाला; पूर्व एडीजी सहित तीन गिरफ्तार

नईदिल्ली, एजेंसी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने कोरोना काल में लोक निर्माण विभाग में हुए दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो कारोबारी और एक लोक निर्माण विभाग के पूर्व एडीजी शामिल हैं। पूर्व एडीजी अनिल कुमार आहूजा पर इन कारोबारियों अक्षितिज बिरमानी और विनय कुमार की कंपनियों को पहले नियमों को ताख पर रखकर टेंडर जारी करने और फिर बिना काम या अधूरे काम के एवज में फर्जी बिलों को पास करने का आरोप है। एसीबी की जांच में यह घोटाला करीब दो सौ करोड़ का है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने बताया कि एसीबी ने एक शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी और निजी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसकी जांच में सामने आया कि पीडब्ल्यूडी ने एलएनजेपी, जीटीबी, बीएसए, जीबी पंत सहित दिल्ली के आठ अस्पतालों में काम

के लिए टेंडर जारी किया था। इसके बाद कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताख पर रखकर इनको टेंडर जारी किए गए। वहीं, जांच के दौरान इस संबंध में कोई भी बिल नहीं दिया गया।

एसीबी की जांच में सेवानिवृत्त एडीजी अनिल कुमार आहूजा और उनके परिवार के खातों में संदिग्ध लेने-देन मिले हैं। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि अनिल कुमार आहूजा और एक प्राइवेट फर्म मैसर्स एवी एंटरप्राइज के बीच सवा करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। एवी एंटरप्राइज ने पांच दिसंबर 2020 को अनिल कुमार आहूजा की बेटी के अकाउंट में भी छह लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। जांच में सामने आया है कि पूर्व एडीजी अनिल कुमार आहूजा ने अपने कार्यकाल में 10 कंपनियों को नियमों को ताख पर रखकर 56 टेंडर जारी किए थे।

जांच में सामने आया कि कंपनियों ने कई जगहों पर काम किया ही नहीं था। जहां काम किया था वह भी पूरा नहीं हुआ था। इस काम के एवज में कंपनी की ओर से विभाग को बिल भेज दिए गए। लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर जारी करने के बाद एक ही दिन में इन निजी कंपनियों से काम करने के लिए कोटेशन मंगवाए गए। टेंडर की बोली लगाई गई और बोली में बिना अंतर देखे एक निर्धारित कंपनी को टेंडर दे दिया गया। यह सब काम विभाग की ओर से एक ही दिन में पूरा कर लिया गया। टेंडर देने में नियमों की अनेदखी की गई। यह काम एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोविड काल के दौरान पीडब्लूडी अफसरों द्वारा अस्पतालों में दो सौ करोड का घोटाला सामने आया है।

दिल्ली में जैन मंदिर में हुआ हादसा, शिखर का हिस्सा टूटकर गिरने से युवक की मौत

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में शुक्रवार को दिगंबर जैन मंदिर के शिखर पर लगे संगमरमर पत्थर का हिस्सा टूटकर मंदिर के नीचे गली में गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय कुणाल जैन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जैन मुनि के दर्शन के लिए शुक्रवार को गली में मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। इस दौरान मंदिर के शिखर का हिस्सा टूटकर गली में खड़े 20 वर्षीय कुणाल जैन पर गिर गया। इसके नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मंदिर का यह हिस्सा अचानक कैसे टूट गया। इसके लिए पुलिस मंदिर के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही मंदिर पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक कुणाल अपने परिवार के साथ घोंडा स्थित जय प्रकाश नगर में रहता था। सुधीर जैन का शर्ट का काम है और मंदिर से थोड़ी दूरी पर पीछे की ओर उनकी फैक्ट्री है। कुणाल अपने पिता के कारोबार में मदद करता था। शाहदरा जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:20 बजे कैलाश नगर की गली नंबर दो में दिगंबर जैन मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर कई जैन भक्त मंदिर के बाहर मौजूद थे।

मैं हूं ना; जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाल लिया एक और मोर्चा

नईदिल्ली, एजेंसी।
मैं हूं ना...; कुछ इसी भाव के साथ सुनीता केजरीवाल एक के बाद एक मोर्चा संभाल रही हैं और पार्टी में पति अरविंद केजरीवाल की कमी को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता अब एक और जिम्मेदारी अपने हाथ में ले चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गैरमौजूदगी में सुनीता हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभालने जा रही हैं। वह अपने ससुराल में पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगी।

सीएम अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आप ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में सुनीता केजरीवाल 27 जुलाई से दो दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगी। वहां अलग-अलग जगहों पर चुनावी सभा करेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हैं। ऐसे में सुनीता खुद को हरियाणा की बहू बताते हुए जेल में बंद पति के हक में वोटिंग की भावुक अपील करती दिखेंगी।

यह पहला मौका नहीं है जबकि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की अहम हिस्सा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जगह रोड शो करके पार्टी के लिए वोट मांगा था। अब फिर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो बीते दिनों उन्होंने हरियाणा चुनाव के प्रचार अभियान व केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करते हुए प्रचार अभियान की शुरूआत की थी। अब 27 और 28 जुलाई को फिर हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार वह उनके परिवार से मिलने पहुंची थीं। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करके उन्हें इस लड़ाई में साथ होने का आश्वासन दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता-पिता से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

वह तो देखने तक नहीं आया, अपने ही बेटे को गोद लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

नईदिल्ली, एजेंसी।
एक महिला अपने पहले पति से हुए बेटे को गोद लेना चाहती है। दोनों का तलाक हो चुका है और महिला ने दूसरी शादी कर ली है। बेटे को दूसरे पिता के साथ अपनाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने याचिका में मांग की है कि पहले विवाह से जन्मे बेटे को उसके बायोलॉजिकल (जैविक) पिता की सहमति के बिना गोद लेना चाहती है, जोकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट (एचएएमए) के तहत अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता दिव्या ज्योति सिंह की ओर से पेश वकील वंशजा शुक्ला ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिसने पूर्व पति को नोटिस जारी किया। महिला ने आरोप लगाया कि सितंबर 2015 में जब वह प्रेग्नेंसी की आखिरी स्टेज में थी, तब पति ने उसे छोड़

दिया और उसके भाई की पत्नी के साथ भाग गया। महिला ने बताया कि पूर्व पति और उसके भाई की पत्नी उसके भाई की चार साल की बेटी के साथ रहने लगे। सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2015 में उनके बेटे के जन्म के बाद वह व्यक्ति उनसे एक बार भी मिलने नहीं आया। दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दायर करने के बाद, सितंबर 2016 में एक पारिवारिक अदालत ने आपसी सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। 2018 में, उस व्यक्ति और सिंह की भाभी ने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी हुआ है। शुक्ला ने बताया कि सिंह ने 2020 में दूसरी शादी की है। उन्होंने कहा, पुनर्विवाह का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वह बच्चे को सामान्य और स्वस्थ परवरिश देना चाहती थीं। सिंह ने एचएएमए की धारा 9(2) का पालन किए बिना सौतेले पिता के साथ अपने बेटे को गोद लेने की अदालत से अनुमति मांगी, जिसके तहत बच्चे को गोद देने के लिए बायोलॉजिकल पिता की सहमति लेना जरूरी है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, जब एचएएमए बायोलॉजिकल पिता की सहमति को जरूरी बनाता है, तो हम उसे बच्चे की कस्टडी छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं, जबकि मां को बच्चे की गार्जियनशिप सौंपी गई है। मामला चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हम (पूर्ववर्ती पति को) नोटिस जारी करेंगे।

कराची दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर, वेनेजुएला का काराकास पहले स्थान पर

कराची , एजेंसी। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान चाहता है कि उसके देश में विदेशी पर्यटक आए, लेकिन फोर्ब्स एडवाइजर की एक लिस्ट ने उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। फोर्ब्स एडवाइजर लिस्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की राजधानी कराची दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर है। कराची को 100 में से 93.12 रेटिंग के साथ पर्यटकों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। यानी कराची में अपराध, हिंसा, आतंकवादी खतरे, प्राकृतिक आपदाओं का डर काफी ज्यादा है। बता दें कि महंगाई और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में लूटपाट और गोलीबारी का घटना आम है। कई रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि कराची रहने लायक शहर नहीं है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को पाकिस्तान में कराची के रक्षा क्षेत्र में दो समूहों के बीच एक-दूसरे पर गोलीबारी के बाद पांच लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, लिस्ट में वेनेजुएला के काराकास को दुनिया का सबसे खतरनाक

शहर माना गया है। इसे 100 में 100 स्कोर दिया गया है। म्यांमार का यांगून तीसरा सबसे खतरनाक शहर है। रिपोर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में सिंगापुर है। सिंगापुर को 100 में से शून्य अंक मिले हैं। इसे इसकी सुरक्षा, न्यूनतम प्राकृतिक आपदा जोखिम और उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की वजह से रैंकिंग मिली है। जापान का टोक्यो शहर दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं कनाडा का टोरंटो शहर तीसरा सबसे सुरक्षित शहर है।

चीन में युवक को मक्खी मारना पड़ा महंगा, डॉक्टरों को निकालनी पड़ी आंख

बीजिंग, एजेंसी। चीन में एक व्यक्ति को अपने चेहरे पर एक कीड़ा (मक्खी) मारने के कारण अपनी आंख गंवानी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि चीन में वू नाम का एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ था तभी उसके चेहरे पर एक मक्खी आकर बैठ गई। उसने भिनभिना रही उस मक्खी को मार डाला। लेकिन एक घंटे के बाद देखा कि उसकी बाईं आंख लाल हो गई है और सूज गई है। देखते ही देखते उसकी आंख में दर्द होने लगा और वह जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने समस्या बताई और डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। लेकिन दवा लेने के बाद भी उसकी आंख का दर्द कम होने की बजाय बढ़ गया और दवा लेने के बाद भी उसकी हालत खराब हो गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के अनुसार चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग के शेनझेन में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर ने बताया था कि गर्मी के मौसम में उसकी आंख आ गई है। लेकिन दवा लेने के बाद उसका दर्द कम नहीं हुआ और उन्हें देखने में दिक्कत होने लगी। जब वह दोबारा किसी दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि उसने जिस मक्खी को मारा था वह संक्रमित मक्खी थी, जिसकी वजह से

उसकी आंख पर उसके संक्रमण का असर हुआ है। अब इस संक्रमण को दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके आंख में गंभीर अल्सर हो गया है। वहीं, संक्रमण वू के मस्तिष्क तक फैलने का खतरा था, और इसलिए डॉक्टरों को उनकी पूरी बाईं आंख को निकालना पड़ा।

डॉक्टरों ने दी ये सलाहः साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया कि युवक के जो संक्रमण हुआ है वह एक नाली में रहने वाले कीट से हुआ है जो मक्खी जैसा दिखता है। जिसका लार्वा अक्सर पानी में रहता है। ये कीड़े आमतौर पर घरों में अंधेरे, नम स्थानों जैसे बाथरूम, बाथटब, सिंक और रसोई में पाए जाते हैं। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि जब कोई कीट आपकी आंखों के पास उड़ता है तो उसको शरीर पर मारने के बजाय इसे धीरे से हटा दें और फिर छूए गए क्षेत्र को साफ पानी या खारे घोल से धो लें।

समुद्र किनारे महिला को मिली एक बोतल, अंदर लिखा था ऐसा मैसेज

रह गई हैरान!

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली एक महिला को समुद्र में एक बोतल मिली, जिसे वह अपने घर ले गई। इस बोतल में लगभग 150 साल पुराना संदेश लिखा हुआ था और उसे देखते ही महिला हैरान रह गई। इस मैसेज को समझने में महिला को 48 घंटे लग गए। पेशे से 49 वर्षीय ग्रीटिंग कार्ड डिजायनर एमी स्मिथ मर्फी इस महीने की शुरुआत में न्यू जर्सी शहर में समुद्री बीच पर टहल रही थीं, जिस दौरान उन्हें पानी में किनारे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी।

एमी ने पास जाकर देखा तो वह एक बोतल थी और जब अंदर देखा तो उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। इसे देखते ही

एमी चौंक गई। उन्होंने कहा, मैंने सोचा यह बहुत अजीब है। यह है क्या? द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एमी उस बोतल को अपने घर ले आई और फिर क्रॉर्क स्क्रू की मदद से उस बोतल को खोला। वह और उनकी भतीजी ने टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए बोतल में पड़े हुए पेपर को बाहर निकाला, जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। एमी ने आगे बताया, हम दोनों को यह समझने में लगभग 48 घंटे का समय लग गया कि पेपर पर आखिर लिखा क्या है? लेकिन जब हमने उसे काफी देर तक देखा और पढ़ा तो समझ में आया कि क्या लिखा हुआ था। एमी और उनकी भतीजी आखिरकार उस मैसेज को पढ़ने में कामयाब हो गईं। उस पर मैसेज लिखा था, याट नेपच्यून ऑफ अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी, अगस्त 6-76। यानी कि बोतल में लिखे हुए मैसेज को छह अगस्त 1976 को नेपच्यून नौका से समुद्र में छोड़ा गया था। हालांकि, इस दौरान एक और बात हैरान करने वाली थी। दरअसल, बोतल समुद्र में 148 साल तक पड़ी रही, लेकिन सिर्फ 15 मील का ही सफर तय कर सकी। बोतल को जहां से फेंका गया था और वो जहां मिली, दोनों के बीच सिर्फ 15 मील का ही डिस्टेंस था। इसके बाद एमी ने बोतल और मैसेज के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उन्हें उसी तरह की बार एंड ब्रदर फिलेडलफिया बोतल मिली जो कि 1990 से पहले की थी। उसी वेबसाइट पर कई और बोतलें भी थीं जोकि 1870 के दशक की थीं। एमी ने कहा कि मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि जहाज पर कौन था, कप्तान कौन था, यह कहां जा रहा था? उन्होंने यह भी बताया कि उसे 1874 का एक आर्टिकल मिला है, जिसमें अटलांटिक सिटी के कैप्टन सैमुअल गेल को नेपच्यून का मालिक बताया गया था।

दामाद को दिया तलाक तो पिता ने काटा बेटी का पैर, पीड़िता ने सुनाई दिल को झकझोर देने वाली आपबीती

कराची , एजेंसी। पाकिस्तान के कराची से एक दिल को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। एक महिला ने शादी तोड़ने के लिए तलाक की अर्जी दाखिल की तो उसके पिता और चाचा ने मिलकर ने उसके साथ बर्बरता की। पिता और चाचा ने गुस्से में उसके पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया। सोबिया बतूल शाह नाम की महिला ने पुलिस को बताया कि उसके अपमानजनक और मार-पिटाई करने वाले पति से तलाक मांगने पर उसके पैर काट दिए गए। उसके पति ने कभी भी अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं ली। कथित तौर पर सोबिया के पिता सैयद मुस्तफा शाह और उसके चाचा सैयद कुर्बान शाह, एहसान शाह, शाह नवाज और मुश्ताक शाह ने कुल्हाड़ियों से सोबिया को घायल कर दिया और उसे खून से लथपथ छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद सोबिया को पुलिस नवाब शाह अस्पताल ले गई। महिला ने पुलिस को आगे बताया कि उसका पति नियमित रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और उसका और उसके दो बच्चों का भरण-पोषण करने में असफल था। सोबिया ने बताया कि जब-जब वो अपने पति की शिकायत घरवालों से करती तो वो अनसुना कर देते।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय
कार्यालय पताः-एच. 21 अंकित अपार्टमेंट ब्रजेश्वरी एनएक्स, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार,आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।